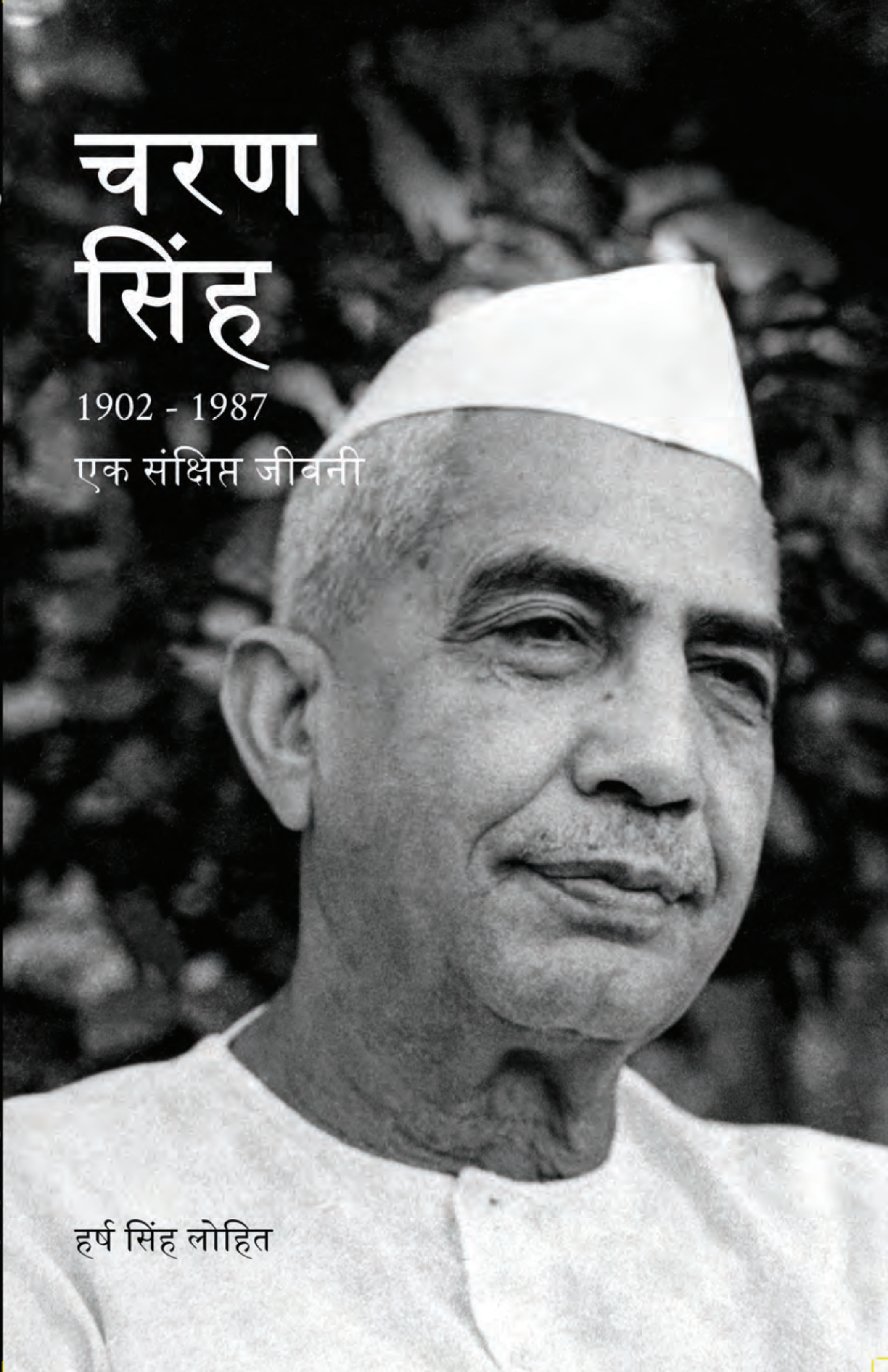

चरण सिंह

1902 - 1987

एक संक्षिप्त जीवनी

हर्ष सिंह लोहित

चरण सिंह

1902 – 1987

एक संक्षिप्त जीवनी

हर्ष सिंह लोहित

कापीराइट © हर्ष सिंह लोहित, 2018

लेखक पॉल आर. ब्रास के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, जिनकी प्रेरणा एवं जिनके द्वारा उत्तर प्रदेश की राजनीति एवं चरण सिंह के जीवन पर किये गये विस्तृत कार्य के अभाव में इस संक्षिप्त जीवन गाथा का लेखन सम्भव न हो पाता।

चरण सिंह अभिलेखागार द्वारा प्रकाशित

www.charansingh.org

info@charansingh.org

अनुवादकः भोला शंकर शर्मा

सुझावों के लिए हम पूरन सिंह वर्मा के आभारी हैं

सर्वाधिािर सुरक्षित। इस प्राशिन ीी ेविल पूर्व अनुमति ेि साथ
पुन: प्रतिुंत, वितररत या प्रसाररत ीयिा जा सतिाै।
अनुमति ेि लिए ृपिया लिखें info@charansingh.org

सौरभ प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, भारत द्वारा मुद्रित।

विषय सूची पृष्ट

आरम्भिक जीवन..5

शुरूआती प्रभाव..9

आज़ादी के लिए संघर्ष..15

राजनीतिक जीवन..19

राजनीतिक शक्ति..23

कांग्रेस के बाद...29

दिल्ली में..35

भारत के प्रधानमंत्री...43

चरण सिंह् की बौद्धिक विरासत.......................................47

जीवन का कालक्रम...53

स्त्रोत...75

अंतिम टिप्पणियां..77

चरण सिंह के पिता मीर सिंह तथा माता नेत्र कौर, 1950

आरम्भिक जीवन

चरण सिंह का जन्म 23 दिसम्बर 1902 को "एक साधारण किसान के यहां छप्पर छवाये मिट्टी की दीवारों से बने घर में हुआ था, जहां आंगन में एक कुंआ था, जिसका पानी पीने और सिंचाई के काम आता था।"[i] संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में एक पट्टेदार गरीब किसान की कच्ची मढ़ैया में पैदा हुआ यह शिशु आज़ाद भारत में देहात की बुलंद आवाज बना।

चरण सिंह नेत्र कौर और मीर सिंह की पांच सन्तानों में सबसे बड़े थे। मीर सिंह 1898 से 1903 तक कुचेसर रियासत के जमींदार के 5 एकड़ के बटाईदार रहे।[ii] जमींदार द्वारा अपनी ज़मीन वापस ले लेने के कारण मीर सिंह को नूरपुर छोड़ना पड़ा और परिवार को भूपगढ़ी (1922 तक) एवं उसके बाद भदौला गांव - दोनों ही मेरठ जिले में हैं - में बसना पड़ा, जहां उन्होंने अंग्रेज़ी फौज में नौकरी कर चुके अपने भाई की मदद से ज़मीन खरीदी, जिसमें अगले वर्षों में और वृद्धि हुई। मीर सिंह का सम्बंध स्थानीय रूप से प्रभुत्वशाली कृषक समुदाय की उस मझोली जाति से था जो कड़ी मेहनत और खेती के तौर-तरीकों में दक्षता के लिए जानी जाती

थी, हालांकि उन्होंने एक भूमिहीन किसान के तौर पर शुरूआत की थी। चरण सिंह के शैशवकाल की इन असामान्य परिस्थितियों ने उनके शिशु-मन पर कुछ ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिनके चलते छोटी जोत वाले, खुदकाश्त खेतिहर किसान परिवारों के प्रति सहानुभूति ने उनके हृदय में जीवन भर के लिए जगह बना ली।

चरण सिंह को अपनी प्राथमिक पाठशाला जाने के लिए रोज़ाना तीन किलोमीटर दूर पैदल जानीखुर्द गांव जाना पड़ता था। स्कूल में उन्हें एक कुशाग्र और विचारशील छात्र के तौर पर जाना जाता था। उनके पिता मीर सिंह थोड़ी-बहुत हिसाब-किताब की जानकारी रखने वाले, प्रकृति के साथ जीवनभर संघर्ष से पैदा होने वाली कृषि कर्मजन्य नैतिकता से युक्त अनपढ़ इंसान थे। एक शाम बालक चरण सिंह को उत्साहपूर्वक परकार(कम्पास) से, जिसे वह स्कूल से लाया था, काम करते देख उन्होंने पूछा कि उनके पुत्र ने यह कहां से पाया? यह बताये जाने पर कि गणित में कमजोर एक सहपाठी को टेस्ट में सवालों के जवाब नकल करने की सहमति देने पर, जिसके कारण वह साथी उत्तीर्ण हो सका, यह उससे मिला है, मीर सिंह ने इससे सख्त नापसंदगी जाहिर करते हुए कहा, "शिक्षक के पीछे दूसरों को नकल कराना बहुत गलत था, और इस गलत कार्य के लिए उपहार स्वीकार करना उससे भी बुरा कार्य था - यह पाप था। किसी को भी जीवन में कुछ पाने के लिए सदैव उत्तम साधनों का ही प्रयोग करना चाहिए।" पश्चाताप में डूबे बालक चरण सिंह ने अगले ही दिन सहपाठी को परकार(कम्पास) लौटा दिया और अपने पिता के इस संदेश को भावी जीवन का मूलमंत्र बना लिया।[iii]

मीर सिंह के पास इतना पैसा नहीं था कि वह गांव की प्राथमिक शिक्षा के बाद चरण सिंह की पढ़ाई जारी रख पाते। उनके सबसे बड़े भाई लखपत सिंह अपने होनहार भतीजे से विशेष प्रभावित थे, सो अब उसकी आगे की शिक्षा का जिम्मा उन्होंने लिया। चरण सिंह ने उन्हें निराश नहीं किया।

वह मेरठ आ गये, जहां उन्होंने 1919 में हाई स्कूल परीक्षा मेरठ गवर्नमेंट हाई स्कूल से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा के लिए वह आगरा चले गये, जहां उन्होंने आगरा कालेज से 1921 में एफ.एस.सी. तथा 1923 में विज्ञान विषय में स्नातक की डिग्री ली। 1925 में (ब्रिटिश, योरोपियन और भारतीय) इतिहास में स्नातकोत्तर (एम.ए.) उपाधि प्राप्त की और अन्ततः 1927 में मेरठ कालेज, मेरठ (जो तब आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था) से कानून (एल.एल.बी.) की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने योरोपियन और भारतीय इतिहास में विशिष्ट ज्ञान अर्जित किया, साथ ही ब्रिटिशकालीन भारत के दीवानी कानून के ढांचे का भी, जिसने गांवों में किसानों के जीवन को बहुत गहरे तक प्रभावित किया था, गहन अध्ययन किया। इसके अलावा उन्होंने अंग्रेज़ी भाषा के ज्ञान में भी दक्षता हासिल की, जिसका सदुपयोग वह आने वाले वर्षों में अपने लेखन में करने वाले थे।[iv]

उस समय जब संयुक्त प्रांत में वयस्क साक्षरता का प्रतिशत 3.1 था और इसमें भी ब्राह्मण, राजपूत, बनिया और कायस्थ जैसी शहरों में जन्मी परम्परागत उच्च जातियों का प्रचण्ड बहुमत था, ऐसे में चरण सिंह जैसे नौजवान के लिए, जो ग्रामीण इलाके की पिछ्ड़ी किसान जाति से था, आगरा में उच्च शिक्षा प्राप्त करना एक दुर्लभ बात थी।[v]

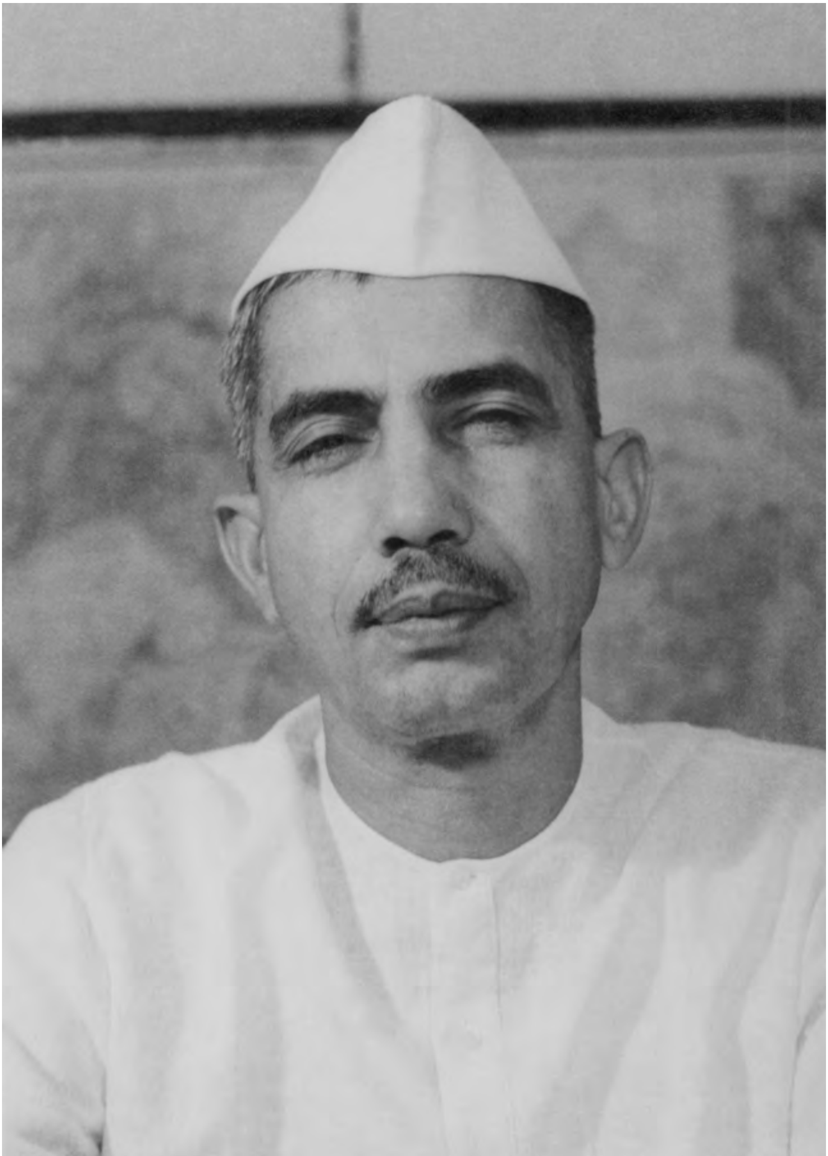

चरण सिंह, 1940

शुरूआती प्रभाव

1920 में जब चरण सिंह एक युवक थे, ग्रामीण परिवेश में बेहद गरीबी, कर्ज़दारी और बेरोज़गारी व्याप्त थी। चरण सिंह के हृदय पर ग्राम्य जीवन के दृश्य हमेशा के लिए अंकित हो गये, जहां अभाव और अन्याय सर्वत्र व्याप्त था और उसका मन-मस्तिष्क कठोर परिश्रम के उन मूल्यों से सराबोर हो गया था, जिसके चलते उसका परिवार अपना अस्तित्व बचा सका और गरीबी से उबर सका। चरण सिंह ने जीवन भर इस तथ्य को हमेशा सहेजे रखा कि उसका पालन-पोषण एक छोटे किसान परिवार में हुआ है और उन मूल्यों से सदैव जुड़ा रहा, जैसे एक सौहार्दपूर्ण पारिवारिक जीवन, अनवरत कठिन परिश्रम, आत्मनिर्भरता और कभी भी समझौता न करने वाली ईमानदारी। इन सब मूल्यों ने उनके बौद्धिक कार्यों और राजनैतिक विचारों के लिए एक उर्वर भूमि तैयार की। बटाईदार-किसानों के अभावों के प्रति उनके आन्तरिक ज्ञान ने उन्हें ब्रिटिश औपनिवेशिकों द्वारा संरक्षित ज़मींदारी-व्यवस्था का सतत निन्दा करने वाला विरोधी बना दिया, और "अन्ततः उन्होंने उत्तर प्रदेश में इसके उन्मूलन में मुख्य भूमिका निबाही"।[vi]

जीवन के आरम्भ में ही चरण सिंह को आर्य समाज और उसके संस्थापक स्वामी दयानन्द ने प्रभावित किया। "उनके चरित्र तथा जीवन में अपने मूल्यों से समझौता करने, सुविधापूर्ण जीवन और चाटुकारिता के लिए कोई जगह न थी। दरअसल स्वामी जी हज़ारों विश्वासों (मतों) के सम्मेलन के बारे में एक किस्सा बारम्बार दोहराने के शौकीन थे। किस्सा यों था": सच्चे धर्म की खोज में लगे एक राजा ने एक धर्मसभा में प्रत्येक धर्म प्रचारक से पूछा कि उनके धर्म में क्या है, उनके धर्म की धारणा क्या है ? उसे एक दूसरे के विचारों का खण्डन करते हुए हजारों परस्पर विरोधी उतर मिले और उसने पाया कि कोई भी उत्तर पूरी तरह से सुस्पष्ट नहीं है, क्योंकि एक-दूसरे को झूठा सिद्ध करने वाली 999 खामियां हरेक में मौजूद थीं। तब एक सच्चे संत ने राजा को उन मूलभूत बिन्दुओं का पता करने को कहा, जिस पर सभी धर्म एकमत थे। ये थे - सत्य, ज्ञान और नैतिकता। संत ने कहा कि मात्र यही सूत्र सच्चे धर्म के परिचायक हैं।" चरण सिंह ने स्वयं अपनी तीन बड़ी संतानों के नाम सत्या, वेद और ज्ञान रखे।

बहरहाल, चरण सिंह अपने जीवन-पथ पर बढ़ते रहे। "...स्वामी जी की बहुमुखी उपलब्धियों में प्रमुख है हमारी राष्ट्रवादी महत्वाकांक्षाओं को सांस्कृतिक एवं संगठनात्मक आधार का उपहार देना।...उन्होंने जाति प्रथा की, उसकी अनगिनत वर्जनाओं और विशेषाधिकारों के लिए ज़बरदस्त भर्त्सना की और व्यक्तिगत तथा आम जीवन में इसके अनाचारों को अनावृत्त किया। उन्होंने योग्यता को श्रेष्ठता का एकमात्र पैमाना माना, (ब्राह्मणवाद के अनुसार) जन्म को नहीं। उन्होंने सामाजिक असमानता की समस्या के समाधान की मांग की, जो बार-बार हमारी राजनीतिक दासता का कारण रही।"[vii] चरण सिंह को युवावस्था में ही एक ऐसे जातिविहीन समाज की स्थापना में दृढ़ विश्वास हो गया था जिसमें केवल व्यक्तिगत प्रयासों और योग्यता के आधार पर सभी के लिए सामाजिक एवं भौतिक विकास और विशेष रूप से लड़कियों के लिए शिक्षा का स्थान हो

तथा धार्मिक रीति-रिवाजों, शोषण करने वाले पुरोहितों, मूर्तिपूजा और जातिगत विभाजनों को स्थाई रूप से समाप्त करना शामिल था।[viii]

इस प्रकार 25 वर्ष की आयु तक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने की उनकी आकांक्षायें आपस में एकमेक हो चली थीं।[ix] दयानन्द ने उनकी सामाजिक और धार्मिक विचारधारा को तथा गांधी जी ने उनकी राजनैतिक एवं आर्थिक दृष्टि को प्रभावित किया।[x] बीसवी शताब्दी के राष्ट्रवादी हिन्दी कवि मैथिलीशरण गुप्त और उनकी पुस्तक 'भारत भारती' एवं 'कबीर' (15 वीं शताब्दी के रहस्यवादी कवि, धार्मिक पाखण्डों की आलोचना करने वाले तथा सभी प्रकार के अंधविश्वासों के विरुद्ध सहज हिन्दी में लिखी रचनाओं के रचनाकार) का भी युवा चरण सिंह पर प्रभाव पड़ा। आज़ादी के आन्दोलन के दौरान अपने भाषणों में अच्छा प्रभाव लाने के लिए वह कबीर के दोहों का प्रयोग करते थे तथा बाद के वर्षों में ये दोहे उन्हें कंठस्थ हो चुके थे।[xi]

चरण सिंह की बौद्धिकता एवं उनकी सार्वभौमिक आर्थिक दृष्टि पर सर्वाधिक दीर्घकालीन प्रभाव मोहनदास गांधी का पड़ा। 1919 से गांधी के दार्शनिक विचार एवं जीवन के दैनिक व्यवहार उनके स्वयं के दर्शन और व्यवहार बनते गये, जो सत्य एवं सत्याग्रह पर आधारित उनकी अहिंसक राजनीतिक क्रांति, सामाजिक परिवर्तन, हरिजनों का उत्थान, आत्म-बलिदान, आत्म-नियंत्रण, सादगी, गांव एवं शिल्पकारों के प्रतिनिधित्वस्वरूप (हाथ से काती हुई) खादी पर आधारित थे। गांधी के विचारों का प्रभाव चरण सिंह के जीवनकाल में दैनंदिन कार्यों पर दृष्टिगोचर रहा।

पहला, निर्धनों के प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने बेहद सादगीपूर्ण जीवन जिया। अपने पूरे जीवन में उन्होंने पारम्परिक खादी का धोती-कुर्ता पहना, भौतिक सम्पत्ति के संचय की ओर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया

और वह निजी तथा लोक-जीवन में विलासिता या दिखावे के हमेशा विरुद्ध रहे। उनका मानना था कि एक राजनैतिक व्यक्ति की निजी और सार्वजनिक जीवन शैली अभिन्न होती हैं।[xii]

चरण सिंह का विश्वास था कि, "भारत जैसा निर्धन देश ऐसे राजनीतिज्ञों को वहन नहीं कर सकता, जो ऊंची मसनदों पर आसीन होकर आदर्शवाद का उपदेश देते हों और व्यवहार उनका भ्रष्टाचारपूर्ण हो।"[xiii]

दूसरे; चरण सिंह ने अपने साठ साल लम्बे सार्वजनिक जीवन के दौरान सदा एक ऐसी आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थापना की वकालत की जो छोटे स्वतंत्र कृषि काश्तकारों एवं ग्रामीणों द्वारा हस्त-निर्मित या ऐसी छोटे स्तर की उत्पादक इकाइयों पर आधारित हो, जिनमें आवश्यकतानुसार ही मशीनों का प्रयोग हो।

महात्मा गांधी ने कहा था, "भारत शहरों में नहीं, गांवों में निवास करता है...भारत देश, जिसमें मानव-श्रम की बहुलता के मुकाबले बले भूमि एवं दूसरे प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो, ऐसी परिस्थिति में उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि केवल कुटीर उद्योग ही हैं जिनमें कम या थोड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है, जो आवश्यकतानुसार रोज़गार उपलब्ध करा सकते हैं और हमारी जरूरतों का निदान बन सकते हैं, न कि आर्थिक वृद्धि के पश्चिमी मॉडल पर आधारित पूंजी प्रधान मशीनीकृत उद्योग, जिनके कारण बेरोज़गारी में वृद्धि होती है तथा सम्पत्ति कुछ ही हाथों में सिमट जाती है, और इस प्रकार अपनी सारी बुराईयों के साथ पूंजीवाद पैर पसारने लगता है।’’

"अधिकांश (किसान-संतानें) अपने गांव या आस-पड़ोस में कुटीर या लघु उद्योग को पूरक या वैकल्पिक पेशे के रूप में अपना सकती हैं, जिसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती।’’

"...राजनैतिक शक्ति प्राप्त करने पर हमने अपनी दृष्टि काफी ऊँचाइयों पर रखने की गलती करते हुए भारी उद्योगों का पूर्णतः पक्ष लिया है। गांधी जी चाहते थे कि देश का निर्माण अपने संसाधनों के अनुसार नीचे से ऊपर की दिशा में किया जाये जिसमें मूलतः गांव या कृषि व दस्तकारी आधार हो और अन्ततः शहर तथा कुछ आवश्यक भारी उद्योग शीर्ष।

"हम भूल गये कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास या देश के करोड़ों लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि इसके अपने घटक संसाधनों से ही सम्भव हो सकेगी (दूसरे शब्दों में मानव अनुपात में सीमित भूमि एवं प्राकृतिक संसाधनों की बंधी सीमाओं के कारण) और लोकतांत्रिक सीमाओं के चलते - जो श्रमिक वर्गों का एक सीमा से अधिक दोहन करने से निषेध करती हैं।

इसलिए वर्तमान स्थिति का निदान यही है कि इसके आर्थिक स्त्रोतों को महानगरीय, औद्योगीकृत एवं पूंजी प्रधान उच्च मध्यम वर्ग की क्रय-शक्ति पर आधारित केन्द्रीयकृत उत्पादन को कृषि, रोजगारोन्मुख और विकेन्द्रित उत्पादन की ओर मोड़ दिया जाये जो कि गांधी जी के शब्दों में, "न केवल आम जनता के लिए बल्कि आम जन के द्वारा भी हो।''[xiv]

लघु उत्पादक एवं लघु उपभोक्ता अर्थव्यवस्था सम्बंधी चरण सिंह के क्रांतिकारी विचार आने वाले दशकों में उनकी सुविचारित पुस्तकों, राजनैतिक घोषणा-पत्रों, विधान-कानूनों एवं राजनीतिक सत्ताकाल के दौरान उनकी सैकड़ों प्रशासनिक कार्यवाहियों में अभिव्यक्त हुए।

चरण सिंह, 1940

U.P.

CH. CHARAN SINGH

MEERUT LEADER GETS ONE YEAR'S R.I.

MEERUT, Dec. 6.

Mr. Charan Singh, M.L.A., and General Secretary, Meerut District Satyagraha Committee, who was arrested on November 29 for offering Satyagraha in village Toogana, Meerut district, was tried today in the jail and sentenced to one year's rigorous imprisonment. He has been placed in "B" class.

Mr. Vishnu Saran Dublish, who was arrested yesterday in Mowana, will be tried in the jail on Saturday December 7.

हिन्दुस्तान टाइम्स, 7 दिसम्बर 1940

आज़ादी के लिए संघर्ष

1921 में जब चरण सिंह आगरा कॉलेज के छात्र थे, गांधीजी के आह्वान पर हरिजनों के उत्थान हेतु, 19 साल के चरण सिंह ने अपने हॉस्टल के वाल्मीकि सफाईकर्मी के हाथों से बना भोजन स्वीकार किया, जिसके लिए कॉलेज में उनका बहिष्कार हुआ किन्तु वह अपने निश्चय पर अडिग रहे।[xv] यह उनकी पहली सांकेतिक कार्यवाही थी जिसने जातिगत पूर्वाग्रह पर प्रहार किया तथा सिद्ध किया कि पूर्वाग्रह से ग्रस्त साथी विद्यार्थियों का विरोध करने के लिए जो वैचारिक साहस और इच्छा-शक्ति चाहिए, वह उनमें थी। बाद में 1932 से 1939 तक गाज़ियाबाद में और 1945 से 1946 तक मेरठ में उन्होंने एक हरिजन युवक को अपना रसोइया रखा। इसके पश्चात 1973 से 1977 के दौरान लखनऊ में एक हरिजन और एक ईसाई रसोइया रखा।[xvi] प्रतीकवाद से परे, अपने लम्बे सार्वजनिक जीवनकाल में उन्होंने अनुसूचित जातियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए अनेकों राजनीतिक कदम उठाये, जिन्हें इस जीवनवृत्त में आगे दर्ज किया गया है। तथापि बहुत पहले ही वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यदि राज्य के महत्वपूर्ण संसाधन कृषि की ओर मोड़ दिये जायें तो स्वतः ही सभी ग्रामीण समुदायों एवं जातियों के लिए समृद्धि के रास्ते खुल जायेंगे

तथा भूमिहीन और निम्नतम जातियों की गरीबी से मुक्ति कृषि से अलग गैर-कृषि आजीविका से होगी।

शिक्षा पूरी करने के बाद 1927 में यद्यपि वह उपयुक्त रोज़गार की तलाश में थे किन्तु उन्होंने बड़ौत जाट स्कूल और लखावटी जाट डिग्री कालेज में प्रधानाचार्य का पद तब तक लेने से इंकार कर दिया जब तक कि वे अपने नाम से 'जाट' शब्द नहीं हटाते। निश्चित ही कालेज प्रबंधन ने ऐसा नहीं किया। यह एक दूसरा उदाहरण था जब उन्होंने भारतीय समाज की विभाजनकारी जातिवाद परम्परा के विरोध में बहस की शुरूआत की।

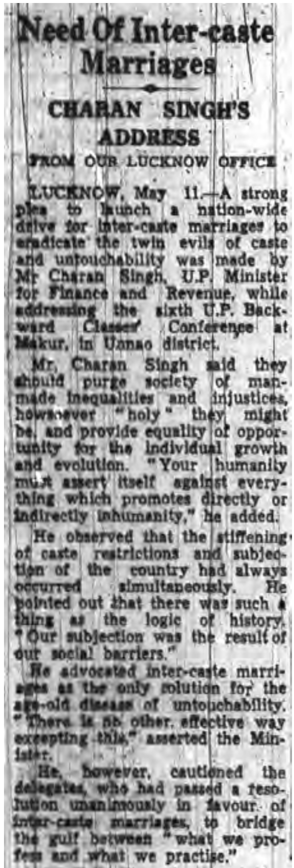

Need Of Inter-caste Marriages

CHARAN SINGH'S ADDRESS

FROM OUR LUCKNOW OFFICE

LUCKNOW, May 11.—A strong plea to launch a nation-wide drive for inter-caste marriages to eradicate the twin evils of caste and untouchability was made by Mr Charan Singh, U.P. Minister for Finance and Revenue, while addressing the sixth U.P. Backward Classes' Conference at Makur, in Unnao district.

Mr. Charan Singh said they should purge society of man-made inequalities and injustices, howsoever "holy" they might be, and provide equality of opportunity for the individual growth and evolution. "Your humanity must assert itself against everything which promotes directly or indirectly inhumanity," he added.

He observed that the stiffening of caste restrictions and subjection of the country had always occurred simultaneously. He pointed out that there was such a thing as the logic of history. "Our subjection was the result of our social barriers."

He advocated inter-caste marriages as the only solution for the age-old disease of untouchability. "There is no other effective way excepting this," asserted the Minister.

He, however, cautioned the delegates, who had passed a resolution unanimously in favour of inter-caste marriages, to bridge the gulf between "what we profess and what we practise."

हिन्दुस्तान टाइम्स
12 मई 1958

1930 में चरण सिंह गाज़ियाबाद में आर्यसमाज के सदस्य थे और धार्मिक अनुष्ठानों में रचे-पगे हिन्दू समाज में सामाजिक बदलाव लाने हेतु किये जा रहे उनके कार्य उस कांग्रेस के साथ अन्तर्मिश्रित हो गये जिसके वह 1929 में ही औपचारिक सदस्य बन चुके थे। 1930 में वह मेरठ जिला बोर्ड के लिए निर्विरोध चुने गये, जहां वह 1935 तक उपाध्यक्ष या उपसभापति रहे और 1940 से 1946 तक मेरठ जिला कांग्रेस के महासचिव या अध्यक्ष रहे। 1928 में उन्होंने गाज़ियाबाद में वकालत (सिविल कानून) की प्रैक्टिस शुरू की, जहां वह मेरठ जाने से पूर्व 1939 तक रहे और 1929 में गाज़ियाबाद जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना की।

1928 में 'साइमन कमीशन' का विरोध एवं उसमें भागीदारी के लिए लोगों को इकट्ठा करना उनकी पहली राजनैतिक कार्यवाही थी। 1932 में उन्होंने कम्युनल अवार्ड (धार्मिक समुदायों एवं अनुसूचित जातियों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र) के विरोध में प्रदर्शन आयोजित किये, हरिजनों के लिए सामूहिक-भोज का आयोजन किया और गांव के कुओं से उन्हें पानी भरवाया, जिसके लिए पारम्परिक रूप से अन्य जातियों द्वारा ऐसा करने की उन्हें मनाही थी।[xvii]

अंग्रेज़ प्रशासन द्वारा 1930 में चरण सिंह को गांधी जी के 'नमक सत्याग्रह' के आह्वान पर लोनी (गाज़ियाबाद) में नमक बनाने पर 6 महीने के लिए जेल भेज दिया गया। नवम्बर 1940 में उनकी दूसरी जेल यात्रा थी, जब व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन के दौरान उन्हें बरेली कारागार में रखा गया। उनकी तीसरी जेल यात्रा अक्टूबर 1942 में "भारत छोड़ो आन्दोलन" के दौरान 13 महीने की थी। इस प्रकार बार-बार रुकावट के कारण उन्होंने शीघ्र ही अपनी वकालत की प्रैक्टिस छोड़ दी और अपना सारा समय राष्ट्र के स्वतंत्रता आन्दोलन के लिए समर्पित कर दिया। इस कठिन दौर में, जब आय का कोई साधन न था और राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए उन्हें बार-बार जेल जाना पड़ रहा था, उनकी पत्नी श्रीमती गायत्री देवी (1925 में विवाह) ने बड़े अभावों के बीच उनके 6 बच्चों की पूरी देखभाल की। बहुधा, चरण सिंह के जेल चले जाने पर परिवार गांव चला जाता था और कुछ माह बाद वापस आ जाता था।

गोविन्द बल्लभ पंत मंत्रिमंडल में पंत जी (दांये से पांचवें) संसदीय सचिव लालबहादुर शास्त्री (बांये से पांचवें) एवं चरण सिंह (दांये से तीसरे) 1946

राजनीतिक जीवन

1937 में मेरठ जिले के (दक्षिण-पश्चिम) से कांग्रेस के टिकट पर संयुक्त प्रांत विधानसभा के लिए पहली बार चुने जाने पर चरण सिंह ने खेतिहरों के जीवन यापन से सम्बंधित विषयों पर प्रश्न उठाते हुए एक सक्रिय विधायक की भूमिका अदा की। उन्होंने संयुक्त प्रांत विधानसभा में 'कृषि उत्पाद विपणन विधेयक' के नाम से एक निजी बिल प्रस्तुत किया, जिसमें व्यापारियों और खाद्यान्न आड़तियों के विरुद्ध कृषि-उत्पादकों के हितों की रक्षा करना एवं किसान सन्तानों और आश्रितों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की 50 प्रतिशत नौकरियां आरक्षित रखने का प्रस्ताव था। साथ ही उसे कांग्रेस विधानमण्डल दल की मीटिंग में रखा और एक 'भूमि उपयोग विधेयक' तैयार किया। ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार बिल के वे अग्रदूत बने, जिसके तहत जमीन जोतने वाले को वार्षिक लगान की 10 गुना राशि सरकारी मालखाने में जमा करने पर जमीन के स्वामित्व का अधिकार मिलने का प्रावधान था। उन्होंने 'यूनाइटेड प्रोविन्स एग्रीकल्चरल एण्ड वर्कमैन डेब्ट रिडम्पशन बिल' को पास कराने में भी रुचि ली, जिसके कारण प्रदेश के हजारों-हजार किसानों को कर्ज़ और

सूदखोरों के चंगुल से छुटकारा मिला और उनके घर-खेत नीलाम होने से बच गए।

1939 में, और पुनः 1947 में उन्होंने उ.प्र. कांग्रेस विधानमंडल दल की विधायी समिति के समक्ष एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उन्होंने किसान संतानों या उनके आश्रितों के लिए सरकारी सेवाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रस्तावित किया, ताकि कृषकों को प्रशासन में उचित हिस्सेदारी मिल सके। 1939 में खेतिहरों के लिए यह एक ऐसी जातिविहीन बीज-व्यवस्था थी जो कालान्तर में 1979-80 के दौरान जनता पार्टी के शासन में अन्य पिछ्ड़ी जातियों (ओ.बी.सी.) पर मंडल आयोग की रिपोर्ट में जाति-आधारित आरक्षण योजना में परिवर्तित हो गई।

1946 में वह दूसरी बार उ.प्र. विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। यह चुनाव उन्होंने केवल जनता से इकट्ठा की गई राशि से जीता था, न कि धनी वर्ग के सहयोग से, और इस राजनीतिक आदर्श पर वह आजीवन कायम रहे। उन्हें गांव और कृषि की दशा का भरपूर ज्ञान था। उनका कभी न हार मानने का जज्बा, उनकी कार्यशैली, कानून की जानकारी और मस्तिष्क के अकादमिक झुकाव ने उन्हें शीघ्र ही राज्य के प्रधान गोविन्द बल्लभ पंत का चहेता बना दिया, जिन्होंने 1946 से 1950 के बीच बनी दूसरी कांग्रेस सरकार में उन्हें संसदीय सचिव (कनिष्ठ मंत्री) नियुक्त कर दिया। 1946 में वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बने और 1954 तक उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के महासचिव रहे।

1947 में उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के समक्ष उन्होंने खेतिहरों (काश्तकार एवं खेतिहर मजदूर, दोनों) के लिए 60 प्रतिशत आरक्षण सम्बंधी टिप्पणी प्रस्तुत करके, जैसे शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के अभिजात्य जमींदारों के खिलाफ एक वर्ग-संघर्ष की घोषणा कर दी। 45 साल के हो चुके चरण सिंह स्पष्टतः अपने पालन-पोषण, चरित्र और आकांक्षाओं की

ओर इंगित करते हुए कहते हैं, "एक किसान संतान में उसके वातावरण के कारण, जिसमें वह पला-बढ़ा होता है, जो दृढ़ इच्छा-शक्ति सम्पन्नता, आंतरिक स्थायित्व, भावनाओं की दृढ़ता और प्रशासनिक क्षमता होती है वह गैर-कृषक या शहर में पली-बढ़ी संतानों के पास नहीं हो सकती, क्योंकि वहां ऐसी भावनाओं को पैदा करने या उनके विकास के अवसर नहीं होते..., जिनका पालन-पोषण आधे-अधूरे कपड़ों में हुआ है, वे ही ग्रामीणों के साथ रात गुजार सकते हैं अथवा उनके सहभागी हो सकते हैं। केवल वे जो आर्थिक हित के सम्बन्धो द्वारा उसके साथ जुड़े हैं सांस्कृतिक ताने-बाने में एकमेव हैं और मनोवैज्ञानिक रूप से निकटतम हैं, वे ही सही तन्तु पर हाथ रख सकते हैं या उस स्विच को दबा सकते हैं जो उनके जीवन को प्रकाशित करेगा और उनके चारों ओर फैले अंधकार को दूर करेगा...,,[xviii]

CHARAN SINGH ELECTED

All Meerut Seats Captured By Congress

(From Our Correspondent)

MEERUT, Feb. 18.

With the announcement of the results to-day of Ghaziabad-Baghpat General Rural constituency o the Provincial Legislative Assembly from which Mr. Charan Singh (Congress), securing 23,928, was declared elected, the counting of votes in all General Muslim Rural Urban constituencies was concluded in Meerut district. His rivals, Mr. Dalsy Ram, M. Mahendra Nath Singh and Mr. Sher Singh, all In-

(Continued at foot of next col.)

हिन्दुस्तान टाइम्स 19 फरवरी 1937

चरण सिंह उत्तर प्रदेश में मंत्री के रूप में, 1952

राजनीतिक शक्ति

अपेक्षाकृत कनिष्ठ स्तरीय होने के बावजूद पं. गोविन्द बल्लभ पंत ने उन्हें ज़मींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार विधान तैयार करने का कार्य सौंपा, जो अन्ततः 1952 में एक कानून के रूप में पारित हुआ। इस प्रकार चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश की 6 करोड़ 70 लाख एकड़ भूमि के काश्तकारों और दसियों लाख भूमिहीनों के सशक्तिकरण और ताकतवर जमींदारों के शोषणकारी एवं परजीवी वर्ग की शक्ति को पूरे प्रदेश से खत्म करने को अपनी राजनीति की प्राथमिक उपलब्धि माना।

वह जमीन, जिस पर बेघरों (अधिकतर अनुसूचित जाति) ने अपने घर बना लिये थे, वे लाखों लोग घरों के मालिक बन गये। स्वयं खेती करने के लिए पट्टेदार से जमीन वापस लेने का अधिकार उत्तर प्रदेश में पूर्व जमींदारों को नहीं दिया गया (जैसा कि अधिकतर अन्य राज्यों में हुआ); और इस तरह लाखों खेतिहरों को राज्य का सहयोगी बनाकर समाज के नवजात लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत बनाया गया। बाद के दिनों में चरण सिंह ने इसका श्रेय पिता समान एवं मार्ग-दर्शक पंत जी की सुदृढ़ राजनीतिक सहमति को दिया। उन्होंने पंत जी (1937 से 1954 के

दौरान) को प्रमुख कारण बताया, जिसके चलते वह ग्रामीण जीवन की पुनर्रचना से सम्बंधित अपने राजनीतिक जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुए।[xix]

1951 से 1967 तक (केवल अप्रैल 1959 से दिसम्बर 1960 की समयावधि को छोड़कर) वह उत्तर प्रदेश में प्रत्येक कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे। उन्होंने राज्य में विधि निर्माण से सम्बंधित जटिल मामलों का गहन अध्ययन कियाः न्याय एवं सूचना; कृषि, पशु पालन और सूचना; राजस्व एवं कृषि; राजस्व एवं यातायात; गृह एवं कृषि; कृषि, पशु पालन, मत्स्य और वन; वन और स्थानीय निकाय मंत्रालयों से सम्बंधित गहन जानकारी अर्जित की। इसने उनमें भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश और बाद में देश के सामने आई अनेकानेक समस्याओं का हल निकालने एवं सम्बंधित मुद्दों पर बेमिसाल नज़रिया कायम करने में सहायता दी।

नागपुर में जनवरी 1959 में अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने खुले तौर पर सामूहिक खेती का विरोध किया और जवाहरलाल नेहरू की नीतियों के विरोध का उन्हें अपने राजनैतिक कॅरियर में निजी तौर पर भारी नुकसान उठाना पड़ा, फलस्वरूप 19 महीने तक उन्हें प्रदेश कांग्रेस सरकार से बाहर रहना पड़ा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैलसिंह ने लिखा है, "नागपुर अधिवेशन में मुझे चौधरी साहब के प्रेरणादायक भाषण को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं चौधरी साहब के लगभग एक घंटे के धाराप्रवाह भाषण से मंत्रमुग्ध था। पंडित जी पूरे मनोयोग से चौधरी साहब के सशक्त भाषण को सुनते रहे और मुस्कुराये भी। जब पंडित जी ने प्रस्ताव पेश किया, उस वक्त पण्डाल में चारों ओर तालियों की आवाजें गूंज रही थीं, किन्तु चौधरी साहब के भाषण के बाद ऐसा महसूस हुआ कि स्थितियां एकदम पलट गई हैं। पंडित जी ने चौधरी साहब के भाषण का उत्तर दिया किन्तु उनसे सहमति न रखते हुए भी,

पंडित जी के व्यक्तित्व की विशालता के समक्ष नत होते हुए हमें उन्हें समर्थन देना पड़ा। मैं जानता था कि अगर मैं पंडित जी के स्थान पर होता, तो चौधरी साहब द्वारा पेश तर्कों की काट करने में कभी सफल न होता।"[xx]

अब तक चौधरी चरण सिंह ने स्वयं को "ईमानदार, एक काबिल प्रशासक, नीतिगत उपलब्धियों के उच्च मानदण्डों के साथ एक सिद्धांतप्रिय और जन-जन, विशेष रूप से कृषक समाज के मुद्दों के प्रति एक समर्पित व्यक्ति के रूप में स्थापित कर लिया था।"[xxi] कैबिनेट से बाहर रहने का सबसे बड़ा लाभ 1959 में उनकी अंग्रेजी पुस्तक 'ज्वाइंट फार्मिंग एक्स-रेड' के प्रकाशन के रूप में सामने आया, जिसमें काश्तकार की छोटी कृषि जोत एवं लघु उद्योग द्वारा विकास पर आधारित गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विचारों के मर्म का पहली बार दस्तावेजीकरण किया गया। इस पुस्तक में नेहरू की और कांग्रेस पार्टी की सामूहिक खेती की स्पष्ट, सशक्त एवं प्रभावशाली आलोचना ने उन्हें ऊँची जगहों पर आसीन लोगों का शत्रु बना दिया।

हालांकि वे भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जवाहरलाल नेहरू की भूमिका के लिए उनकी सराहना एवं बहुत सम्मान करते थे लेकिन भारत के विकास से सम्बंधित उनके विचारों को वे सही नहीं मानते थे। इस महान आदमी के निधन के काफी बाद उन्होंने कहा, "नेहरू जी भारत में पैदा हुए थे किन्तु भारत की मिट्टी से पैदा नहीं हुए थे;,,[xxii] और उन्होंने नेहरू की उन आर्थिक नीतियों का खुलकर विरोध किया जिनके अनुसार वे "भारत का निर्माण ऊपर से नीचे की ओर उद्योगपतियों, प्रबंधकों और तकनीशियनों द्वारा नगर केन्द्रित अर्थव्यवस्था के माध्यम से करना चाहते थे", जबकि "गांधी जी भारत का निर्माण ग्राम केन्द्रित अर्थव्यवस्था द्वारा नीचे से ऊपर की ओर यथा निर्धनतम एवं कमजोर तबके को लेकर करना चाहते थे।,,[xxiii]

उन्होंने आज़ाद भारत के प्रथम गृहमंत्री सरदार बल्लभ भाई पटेल को अपना आदर्श नेता माना "...एक सक्षम प्रशासक के लिए आवश्यकता होती है एक स्पष्ट नीति की और उसको पूरे मनोयोग से कार्यान्वित करने की इच्छा-शक्ति की। जो इन नीतियों को लागू करते हैं, वे लोग पूर्णरूपेण ईमानदार और काम के दौरान मिलने वाले प्रलोभनों और दबाव से खुद को अलग रखने में सक्षम होने चाहिए।"[xxiv] चरण सिंह के लिए पटेल एक ऐसे कांग्रेसी नेता थे, जो ग्रामीण भारत की आकांक्षाओं के अनुरूप थे, सुदृढ़ थे और अंग्रेजों के जाने के बाद भारत की तमाम समस्याओं और उनके समाधान की सार्थक दृष्टि रखते थे। "सरदार पटेल के हृदय में गरीबी, भ्रष्टाचार और झूठ के प्रति गुस्सा था। जब भी कभी सिद्धान्तों की रक्षा की बात हो, सरदार पटेल अपने सगे सम्बंधियों को भी नहीं बख्शते थे।"[xxv]

सरकार में दो दशक के कार्यकाल ने चरण सिंह को प्रशासन में कुशलता लाने वाले एक अभियानी योद्धा की तथा काहिली और भ्रष्टाचार से समझौता न करने वाले और कार्यालय में लम्बे समय तक कठोर परिश्रम करने वाले एक समर्पित लोकसेवक की प्रतिष्ठा दी। फरवरी 1953 में राज्य के राजस्व विभाग की अग्रिम पंक्ति के कर्मचारीगण पटवारियों ने जमींदारों की शह पर अपनी रोज़गार शर्तों सम्बंधी शिकायतों की आड़ लेकर सरकार को दबाव में लाने के लिए एक राज्यव्यापी हड़ताल शुरू करी, साथ ही सरकार को इस्तीफे सौंप दिये। पटवारियों का असली मकसद ज़मींदारी उन्मूलन में बाधा डालना था। राजस्व मंत्री के नाते चरण सिंह ने उनकी प्रतिरोधी मांगों के आगे झुकने से इंकार कर दिया और दो बार चेतावनी देने के बाद 27 हज़ार पटवारियों के इस्तीफे स्वीकार किये। "सही रुख यही है जिसे एक सरकार को ऐसी परिस्थिति में अपनाना चाहिए, कि यदि कर्मचारियों की मांगें या अन्य लोगों की मांगें उचित हैं, तो जानकारी मिलने पर उन्हें जल्द से जल्द स्वीकार किया जाये और यदि वे अनुचित हैं तो किसी भी हड़ताल, सत्याग्रह या आन्दोलन के

किसी अन्य रूप की परवाह न करते हुए उन्हें न माना जाये... नेतृत्व के बिना लोकतंत्र निरंकुशता है।"[xxvi] पटवारियों के स्थान पर उन्होंने निर्वाचित ग्राम निकायों के प्रति उत्तरदायी लेखपाल के पदों का सृजन किया और इन पदों को भरे जाने के लिए अनुसूचित जनजाति से 18 प्रतिशत लोग नियुक्त किये जाने सम्बंधी निर्देश दिये, यद्यपि उचित अभ्यार्थियों के अभाव से यह योजना पूर्णतया सफ़ल ना हो सकी।

1953 में राजस्व एवं कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम को उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश कर पारित कराया और इसे 1954 से लागू कराया। इसके उपरांत उन्होंने सीलिंग के फलस्वरूप बड़े किसानों से प्राप्त भूमि को हरिजनों को आवंटित किये जाने सम्बंधी नीति बनाई। उन्होंने साढ़े तीन एकड़ भूमि के स्वामित्व वाले किसानों को भूमि राजस्व-कर से भी मुक्त कर दिया।

उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नौकरशाह चरण सिंह का बहुत आदर करते थे, क्योंकि उनकी दृष्टि में "वे एक गम्भीर, बेहद ईमानदार और भ्रष्ट अधिकारियों के लिए आतंक थे।" "...1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए चरण सिंह ने साम्प्रदायिक दंगाग्रस्त राज्य के रूप में कुख्यात उत्तर प्रदेश को साम्प्रदायिक दंगों से मुक्त कर देने का अभूतपूर्व जादू कायम कर दिया। यह भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, ईसा और महात्मा गांधी के उपदेशों के भाषण देने से नहीं हुआ, यह केवल देश के कानून को प्रभावी रूप से लागू करने के बल पर हुआ।"[xxvii] "पहला और सबसे प्रभावी कदम यही होना चाहिए कि मुख्यमंत्री पोस्टिंग एवं स्थानांतरण से स्वयं को विलग कर ले और पुलिस के अभियानों में कोई दखल न दे। यही कारण था कि चरण सिंह 1970 में उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगों का उन्मूलन करने में सफल रहे। ...जिन पुलिस अधिकारियों ने उन पर राजनीतिक दबाव डालना चाहा, उनसे कठोरता से निपटते हुए उन्होंने पुलिस में कठोर अनुशासन बनाये रखा।"[xxviii]

मुख्यमंत्री के रूप में चरण सिंह, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 3 अप्रैल 1967

BKD will contest all U.P. seats

Hindustan Times Correspondent

New Delhi, June 3—The Bharatiya Kranti Dal National Executive by a resolution today decided to contest almost all seats in the U.P. mid-term poll.

By another resolution, the party

हिन्दुस्तान टाइम्स 4 जून 1968

कांग्रेस के बाद

कांग्रेस पार्टी में गुटीय कुचक्रों के चलते जिनमें वह शायद ही कभी आगे निकल पाये होंगे 1967 में चरण सिंह 17 अन्य विधायकों के साथ कांग्रेस से अलग हो गये और भारतीय जनसंघ एवं समाजवादियों के साथ गठबंधन में संयुक्त विधायक दल (एस.वी.डी.) की पहली गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री बने।*

उनकी सरकार गिर गई; 1968 जनवरी में प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी के उत्तर प्रदेश दौरे पर राजनारायण (समाजवादी पार्टी के नेता, जो एस.वी.डी. का महत्वपूर्ण घटक थी) द्वारा उनके (इंदिरा गांधी) विरुद्ध

* "मैं राजनीतिक जीवन में उन कुछेक व्यक्तियों का प्रशंसक रहा हूँ, जो राजनीति को एक धर्म के रूप में देखते हैं, व्यक्त लक्ष्यों को पाने के लिए सुस्पष्ट उपक्रम करते हैं और इस क्रम में स्वयं को लाभान्वित नहीं करते।" xxi प्रस्तावना। "कि वह (चरण सिंह) अनथक रूप से अपने पूरे राजनीतिक जीवनकाल में सत्ता और पद पाने के लिए उपक्रम करते रहे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन, .. उनके और उनके विरोधियों के द्वारा सत्ता प्राप्ति के लिए किये गये उपक्रमों के बीच एक अन्तर था, कि उनके पास निर्धारित नीतियां थीं, जिनका उपयोग वह देश और देशवासियों की भलाई में करना चाहते थे।" पृष्ठ 434, एन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ: चरण सिंह एण्ड कांग्रेस पालिटिक्स, 1937 से 1961, खण्ड 1, द पॉलिटिक्स ऑफ नार्दर्न इंडिया। सेज पाब्लिकेशंस इंडिया, नई दिल्ली। ब्रास, पॉल 2011।

हिंसक प्रदर्शन किये जाने पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। स्वतंत्र भारत में जन-विरोध के ऐसे तौर-तरीकों को चरण सिंह नापसंद करते थे - उनका मानना था कि स्वयं भारतीयों द्वारा चलाई जा रही सरकार में जन-अवज्ञा के ऐसे तौर-तरीके अप्रासंगिक एवं आपराधिक हैं।

1968 में चरण सिंह ने बिहार, उड़ीसा, बंगाल और राजस्थान के पूर्व प्रमुख कांग्रेसियों के साथ जुड़कर एक नये राजनीतिक दल - भारतीय क्रांति दल (बी.के.डी., इंडियन रिवोल्यूशनरी पार्टी) के गठन में सहायता की। इस समय से जीवन के अंतिम दौर तक उनका ध्यान राजनैतिक दलों को कांग्रेस के विरोध में एकजुट करने पर केन्द्रित रहा, जिससे कि कांग्रेस 1967 के चुनाव में लोकप्रिय वोटों की अल्पमत प्राप्तकर्ता बनी और विपक्ष के बिखराव के कारण ही राज्य विधानसभा में बहुमत में आई। बी.के.डी. ने उत्तर प्रदेश में अन्ततः अपने मूल जनाधार - छोटे और मझोले किसानों - का सैद्धांतिक समर्थन हासिल किया। 1969 में मध्यावधि चुनाव में बी.के.डी. ने 98 सीटें और 21 प्रतिशत लोकप्रिय वोट प्राप्त कर कांग्रेस के मुकाबले दूसरा महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया; वह भी बिना किसी स्थापित राजनीतिक संगठन का सहारा लिये या आम जनता के अलावा बिना किसी की वित्तीय मदद के। 1969 में कांग्रेस के ऐतिहासिक विभाजन के बाद इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बनी नई कांग्रेस के साथ एक असहज और अल्पकालिक गठबंधन द्वारा चरण सिंह 1970 में दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।

चरण सिंह के मन में सार्वजनिक जीवन में लगातार उजागर और बढ़ रहे भ्रष्टाचार के प्रति सदैव चिंता रही। वह अक्सर कहते थे, "यथा राजा तथा प्रजा'' की तर्ज पर जनता राजा का अनुसरण करती है। इसलिए सार्वजनिक जीवन में नेताओं को नैतिकता का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। भारत में राष्ट्रीय चरित्र या इसकी कमी को वह तुलनात्मक रूप से जापान जैसे देश से प्रतिकूल पाते थे, जहां अग्रणी कार्य संस्कृति के साथ

ईमानदारी से काम करने की नैतिकता थी।[xxix] "भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ गया है। मैं इसका जिम्मेदार नौकरशाही को न मानकर राजनेताओं को मानता हूँ। मेरा अनुभव यह रहा है कि अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाईयों को राजनैतिक नेतृत्व परिभाषित करता है, क्योंकि वे घोड़े और घुड़सवार की तरह निर्देशों पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हैं। घोड़ा बहुत जल्दी समझ लेता है कि उसकी पीठ पर बैठा सवार घुड़सवारी जानता है या नहीं, और यदि वह नहीं जानता है, तो तुरन्त उसे गिरा देता है... भ्रष्टाचार शिखर से शुरू होता है, न कि नीचे से।"[xxx] चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश जैसे अराजक राज्य में, जिसे वह अशासनीय मानते थे, अपने प्रशासनिक उपायों से व्यवस्था कायम करना जारी रखा। 1967 में उनके मंत्रिमण्डल ने एक आदर्श भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम *The Uttar Pradesh Public Men Enquiries Ordinance* पारित किया। 1970 में उन्होंने भ्रष्टाचार के दस्तावेजी सबूतों के आधार पर पूरे प्रदेश की 51 जिला परिषदों को भंग कर दिया।

चरण सिंह जिन सिद्धांतों को मन से पसंद करते थे उनकी उन्हें एक लम्बी स्मृति थी, जिसके चलते उन्होंने 1939 में कांग्रेस से की गई अपनी अपील को याद किया, अर्थात "शिक्षा संस्थान में या सार्वजनिक सेवा में प्रवेश करते समय एक हिन्दू अभ्यार्थी से - अनुसूचित जाति को छोड़कर - उसकी जाति के बारे में नहीं पूछा जाना चाहिए।" 1970 में उनके मंत्रिमण्डल ने एक कानून का अनुमोदन किया कि ऐसे किसी भी शिक्षा संस्थान से, जिसके नाम में किसी विशिष्ट जाति, समुदाय का उल्लेख हो, उसकी सारी वित्तीय सहायता राज्य वापस ले लेगा। फलस्वरूप सभी संस्थानों ने अपने जातिगत या समुदायगत नामों को हटा दिया और रास्ते पर आ गये।

29 अगस्त 1974 को उन्होंने कांग्रेस का राष्ट्रीय विकल्प देने के उद्देश्य से बी.के.डी., स्वतंत्र पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, उत्कल कांग्रेस, राष्ट्रीय

लोकतांत्रिक दल, किसान मजदूर पार्टी और पंजाबी खेती-बाड़ी ज़मींदारी यूनियन का विलय कर भारतीय लोक दल का गठन किया।

1967 में इंदिरा गाँधी ने चरण सिंह के कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्हें कांग्रेस में पुनः शामिल करने के कई प्रयास किये। ये प्रयास बिना किसी नतीजे पर पहुंचे समाप्त हो गए - दोनों प्रबल व्यक्तित्व थे और भारतीय अर्थव्यवस्था पर पूर्णतः विपरीत दृष्टिकोण होने के चलते एक-दूसरे के समक्ष झुकने को तैयार न थे। इंदिरा गाँधी के बढ़ते अधिनायकवादी और वंशवादी कारगुजारियों के विरोध के चलते अन्ततः 1975-77 में लागू किये गये आपातकाल (इमर्जेन्सी) के फलस्वरूप दोनों के निकट आने का अवसर फिर कभी न बना।

1971 में इंदिरा गांधी के 'गरीबी हटाओ' के लोकप्रिय नारे और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस द्वारा धन के भारी इस्तेमाल के चलते चरण सिंह मुजफ्फरनगर से भारतीय संसद का चुनाव हार गये।[xxxi] 1974 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के ख़िलाफ़ भारतीय लोकदल प्रमुख राजनीतिक विपक्षी दल के रूप में बना रहा और 1971 से 1975 के मध्य तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में वे नेता विरोधी दल रहे। इस दौर में उनका पूरा ध्यान सम्पूर्ण विपक्ष को एक साझा कार्यक्रम के अन्तर्गत कांग्रेस के राजनीतिक विकल्प के रूप में एक राजनीतिक संगठन के तौर पर स्थापित करने में रहा।

चरण सिंह मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए, लखनऊ ,16 फरवरी 1970

10-member BKD Ministry assumes office in U.P.

From Kapil Varma
Hindustan Times Correspondent

Lucknow, Feb. 17—Mr Charan Singh, the 68-year-old BKD leader, returned to power today exactly after two years with his swearing-in by Governor B. Gopala Reddy as Chief Minister at the head of a 10-man single-party Ministry.

Six other Cabinet Ministers—Mr Sripat Misra, Mr Dharam Singh, Mr Virendra Varma, Mr Shiv Raj Singh, Mr Anwar Ahmad and Mr Balbir Singh—and three Deputy Ministers—Mr Om Prakash Singh, Mr Ram Prasad Deshmukh and Mr Ram Kinkar, were also administered the oath of office and secrecy.

Mr Charan Singh later told newsmen the Ministry would be expanded in March or April.

As is known, his minority Government is supported by the numerically bigger group of the "new" Congress.

The brief swearing-in ceremony, which was held at Raj Bhavan within 90 minutes of the Governor inviting the BKD leader to form the Ministry, was attended by "New" Congress Legislature Party leader Kamlapati Tripathi with some of his partymen, and Speaker A. G. Kher. But none of the leaders of the alliance led by the "Old" Congress was present. A large number of BKD supporters, however, attended the ceremony and

Mr Charan Singh

हिन्दुस्तान टाइम्स, 18 फरवरी 1970

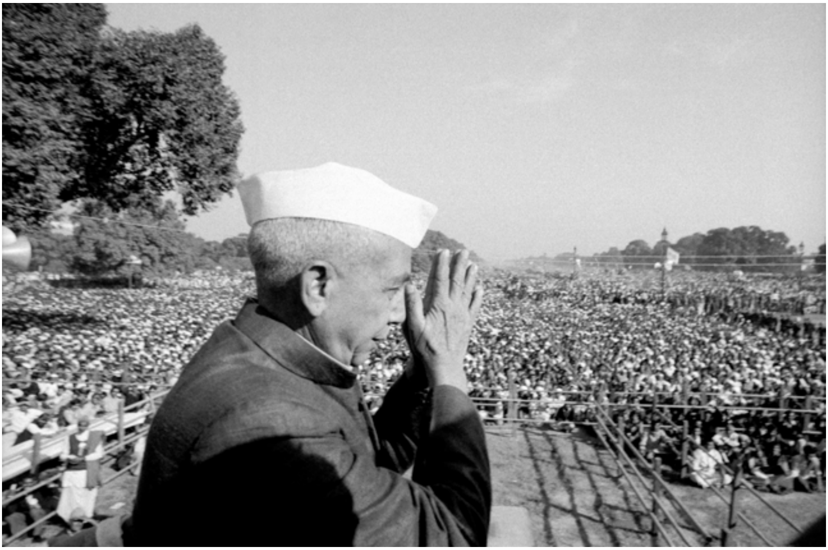

नई दिल्ली में बोट क्लब पर किसान रैली, 23 दिसम्बर 1978

दिल्ली में

25 जून 1975 से 25 मार्च 1977 के बीच इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल के दौरान, जबकि अधिनायकवादी शासन के चलते सभी नागरिक स्वतंत्रताएं छीन ली गयी थीं, चरण सिंह को तमाम विपक्षी राजनेताओं एवं भारत में फैले हज़ारों-हजार राजनीतिक कार्यकर्ताओं की तरह दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद कर दिया गया था। आपातकाल की ज्यादतियों और गणतंत्र संस्थानों के विनाश का ऐसा उदाहरण भारत के इतिहास में अन्यत्र कहीं नहीं मिलता है। धीरे-धीरे इंदिरा गांधी का शासन तानाशाही में बदलता गया, जिसमें किसी भी प्रकार का विरोध नाकाबिले बर्दाश्त था और इसका सबसे तीखा सामना और विरोध भी उत्तर प्रदेश में चरण सिंह ने किया। जेल से रिहाई के बाद चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल के उत्तरी भारत के खेतिहरों के बीच व्याप्त राजनैतिक जनाधार ने उसे बी.एल.डी., जनसंघ और कांग्रेस (ओ) के गठबंधन से बनी जनता पार्टी का प्रमुख घटक बना दिया, जिसने 1977 के आम चुनावों में कांग्रेस को पराजित कर, इंदिरा गांधी का अस्थाई पतन कर दिया और इस प्रकार आज़ाद भारत में पहली बार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केन्द्र में गैर-कांग्रेसी सरकार बनी। इस जनता पार्टी को भारतीय

लोकदल ने योगदान के रूप में अपना चुनाव चिन्ह, ‘हल जोतता किसान’ तो दिया ही, साथ ही उत्तर भारत के, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य के मध्यवर्गीय खेतिहर समुदाय का समर्थन और गांधीवाद से प्रेरित कृषिउन्मुख एवं कुटीर उद्योगोन्मुख विकास का विचार भी दिया। जनसंघ के बराबर ही संसद सदस्यों की संख्या में भारतीय लोकदल पार्टी का योगदान 80 से 100 सांसदों का था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अन्ततः आर्थिक नीति पर जनता पार्टी समितियों के चेयरमैन के रूप में चरण सिंह के पास समतामूलक विकास के आदर्श को विकसित करने सम्बंधी भारत की नीतियों को प्रभावित करने की शक्ति आ गयी थी।... "अतएव जब तक यह देश पूँजीवादी विकास के वर्तमान नमूने से प्रतिवद्ध रहता है, जिसमें कि भारी लागत से पूँजी आधारित आधुनिक उद्योग स्थापित किये जाते हैं... बेरोज़गारी बढ़ती जायेगी और पूंजी कुछ हाथों में इकट्ठी होती जायेगी... इस बंधन से छुटकारा पाने का एकमात्र और सही रास्ता है... औद्योगीकरण के मौजूदा ढांचे से नाता तोड़ा जाये और गांधीवादी रास्ता अपनाया जाये...,,[xxxii]

चरण सिंह ने अब तक स्वतंत्र भारत के खेतिहर कृषक वर्ग के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया था, फिर भी वे भूमिहीनों एवं निम्न जातियों के जीवनयापन एवं समता के मुद्दे पर चिंतित रहे। उन्होंने बहुत पहले यह जान लिया था कि भारत की मूल समस्या भूमि का बेहद कम होना और जनसंख्या का बेहद ज़्यादा होना था, और भूमि हदबंदी कानूनों के तहत बड़े जमींदारों से प्राप्त भूमि का समान वितरण भी भूमि की कमी की समस्या का पूर्ण हल नहीं था। साथ ही बढ़ती जनसंख्या के बोझ के चलते खाद्यान्नों की बढ़ती मांग का मतलब था- कृषक समाज की भूमि का रकबा भी अनार्थिक होते जाना। इस मुद्दे पर ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक हो गया था, क्योंकि उत्तराधिकार के नियमों के कारण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने पर आर्थिक भूमि जोत भी बंटवारे

के बाद अनार्थिक होती जाती थी। भूमि के इस मुश्किल हल होने वाले मुद्दे से लड़ने के बजाए उन्होंने इसका हल गांधीवाद की तर्ज पर कृषि से बाहर भूमिहीन श्रमिकों तथा गांव के गैर-खेतिहरों में खोजा। जहां वह कर सकते थे, उन्होंने भूमिहीनों को भूमि का वितरण तो किया परन्तु अनेक कानूनी खामियों और छल के कारण बहुत से स्थानों में भू-स्वामियों ने अपनी जमीनों पर पुनः अधिकार कर लिया और इसीलिए उन्होंने भूमिहीनों को कृषि से हटाने के लिए उनकी सहायता में एक राज्य समर्थित आन्दोलन चलाने की वकालत की। वे जहां शहरों और उद्योगों के बजाए कृषि क्षेत्र में अधिक निवेश के पक्षधर थे, वहीं उनका यह भी मानना था कि सरकार अनौपचारिक क्षेत्र में गैर-कृषि पेशों के प्रोत्साहन के लिए निवेश करें - उदाहरण के लिए ब्रिटिश काल से हतोत्साहित भारत के गांवों की परम्परागत हस्तकला को पुनर्जीवित किया जाये और गांवों में तथा उनके आसपास कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना हो, ताकि भूमिहीनों को रोज़गार मिल सके। उनके सपनों का भारत छोटे उत्पादकों और छोटे उपभोक्ताओं का देश था।

चरण सिंह जनता पार्टी सरकार में मार्च 1978 से जुलाई 1979 तक गृहमंत्री रहे। मंत्री के रूप में उन्होंने 1977 में पुलिस आयोग का गठन किया। 1902 के बाद अपने आप में यह आपराधिक न्याय व्यवस्था की पहली व्यापक समीक्षा थी।[xxxiii] आयोग को अनुशंसा करनी थी कि "पुलिस द्वारा शक्ति का दुरुपयोग, प्रशासनिक या नौकरशाही द्वारा पुलिस का दुरुपयोग तथा राजनीतिक या कोई अन्य दबाव और किसी भी प्रकार के गैर-कानूनी मौखिक आदेश, कैसे रोके जायें।'' "एन.पी.सी. की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुशंसा पुलिस को राजनैतिक और नौकरशाही के गैर-कानूनी हस्तक्षेप के चलते अपमान से बचाने पर केन्द्रित थी।''[xxxiv] चरण सिंह किसी भी धर्म की साम्प्रदायिकता का विरोध करने वाले राष्ट्रवादी थे। धर्म के आधार

पर वे भारत के विभाजन के घोर विरोधी थे। 1947 में, एक अलग देश के रूप में मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का निर्माण उनके लिए एक असहज स्थिति थी, जहां मुसलमानों पर भारत के प्रति वफादारी का भारी दायित्व होगा और बहुसंख्यक समुदाय पाकिस्तान में रह रहे अल्पसख्यक हिन्दुओं से स्वयं को सम्बद्ध करने को बाध्य होगा। हालांकि उनका यह भी मानना था कि स्वतंत्र भारत में सभी अल्पसंख्यकों को सुरक्षा का अहसास कराना हिन्दू बहुसंख्यकों का दायित्व होगा। इसी उद्देश्य से जनवरी 1978 में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के सन्दर्भ में उन्होंने "अल्पसंख्यक आयोग'' की स्थापना की, "जिसका उद्देश्य था धर्मनिरपेक्ष परम्पराओं को संरक्षित करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना... और संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध कराये गये सभी सुरक्षात्मक नियामकों को लागू करना।''[xxxv]

23 दिसम्बर 1978 को चरण सिंह के जन्म दिन के अवसर पर बोट क्लब नई दिल्ली में, स्वतंत्र भारत में किसानों की सबसे बड़ी रैली आयोजित की गई। यह शहरी समाज को इस बात का इशारा था कि अब गांव राजनैतिक शक्ति के लिए और इंतजार नहीं करेंगे।[xxxvi]

केन्द्रीय मंत्रिमण्डल से छह महीने बाहर रहने के बाद, चरण सिंह जनवरी 1979 से जुलाई 1979 के बीच उप-प्रधानमंत्री और साथ ही वित्तमंत्री रहे। वित्तमंत्री के रूप में उन्होंने कृषि और ग्रामीण विकास के लिए संस्थागत ऋण की समीक्षा के उद्देश्य से मार्च 1979 में बी. शिवरामन कमेटी का गठन किया, जिसने बाद में 1982 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की नींव रखी। केन्द्रीय बजट में श्रमिक आधारित उद्योग, ग्राम विकास और कृषि पर सर्वाधिक ध्यान दिया, क्योंकि यह सभी के द्वारा मान्य था कि केवल इसी तरीके से देश में गरीबी और बेरोज़गारी का उन्मूलन किया जा सकता है।

हालांकि इस प्रक्रिया में "मैंने भारी उद्योग और बुनियादी ढांचे की अनदेखी नहीं की। इसके ठीक विपरीत, मैंने उनको सकारात्मक रूप से प्रोत्साहित किया लेकिन मेरी उन उद्योगों से कोई सहानुभूति नहीं है जो अमीरों की इच्छाओं को पूरा करते हैं। हमारे पास ऐसे उत्पादन के लिए कोई जगह नहीं है जो अमीरों के लिए हो, और इस प्रकार समाज में व्याप्त विषमताओं को बढ़ाता हो।''[xxxvii] उन्होंने कच्चे तम्बाकू से आबकारी शुल्क हटाकर सिगरेट और बीड़ी पर लगा दिया और इस प्रकार "लाखों किसानों को टैक्स इंसपेक्टरों के शिकंजे से बचा लिया'' तथा धनी समाज के लिए अलोकप्रिय फैसले के रूप में पूंजी लाभ कर को पुनः लागू कर दिया।[xxxviii] इसके साथ ही गांव के बेरोज़गार युवाओं के लिए श्रम विनिमय के रूप में अनाज उपलब्ध कराने की दृष्टि से "काम के लिए अनाज'' कार्यक्रम आरम्भ किया और इसके लिए उदारता से धन दिया। यह गरीबनवाज़ मनरेगा कार्यक्रम का आगाज़ था और इस प्रकार सरकार के सरप्लस खाद्यान्न भण्डार से लाखों टन खाद्यान्न का उपयोग रोज़गार पैदा करने के लिए किया गया।[xxxix]

1947 में भारत की आज़ादी के बाद दिल्ली में स्थापित पहली कांग्रेस-विहीन सरकार की सत्तारूढ़ जनता पार्टी का जुलाई 1979 का विभाजन हो गया। चरण सिंह को छोड़, जनता पार्टी के प्रमुख भागीदार दलों के नेतृत्व को गठबंधन सरकार बनाने और चलाने का अनुभव न था। भिन्न-भिन्न राजनैतिक हितों तथा व्यक्तिगत स्वार्थ के अलावा जनता पार्टी अनेक विरोधी विचारधाराओं - समाजवादियों से लेकर हिन्दुवादी - का समावेशन थी। संयुक्त एकल दल का मोर्चा होने के बावजूद यह किसी से न छिपा था कि जनता पार्टी अनेक घटकों का गठबंधन है, जिसमें कोई भी अपनी अलग-अलग पहचान एक संगठन के रूप में विलय करने को तैयार न था। प्रत्येक घटक राज्यों में और केन्द्र में सत्ता-केन्द्र बनने के लिए प्रयासरत था और जहां जनता पार्टी की सरकारें थीं, इसके लिए वह

अपनी ही सरकारों के बहुमत को अस्थिर करने में लगा रहा। केन्द्र और राज्य स्तर पर पार्टी संगठन पर नियंत्रण के लिए इन दलों ने दूसरे दलों से भी अदल-बदल कर गठबंधन किये। आखिर में, नेताओं की महत्वाकांक्षाओं और व्यक्तित्व के टकराव का प्रश्न भी था जिसमें प्रत्येक अपने द्वारा राष्ट्र की सेवा में अपने अभिलेख पर गौरवान्वित था। हालांकि चरण सिंह ने अपने घटक दल के हितों की उपेक्षा करते हुए समायोजन पर बल दिया परन्तु उनके अपने घटक दल बी.एल.डी. द्वारा संचालित बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा में जनता पार्टी की राज्य सरकारों पर राजनैतिक आक्रमण लगातार जारी रहा।[xl] इसके साथ ही पार्टी संगठन पर कब्जे के लिए निहित अन्तर्कलह ने विषम रूप धारण कर लिया और विद्यमान विभाजन गहराता गया। यदि पं. गोविन्द बल्लभ पंत जैसा उदारमना और सबको साथ लेकर चलने वाला नेता इतिहास ने जनता सरकार को उपलब्ध कराया होता, तो शायद भिन्न-भिन्न हितों और विचारधाराओं के असहज गठबंधन के बावजूद पार्टी और सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया होता। दुर्भाग्य से मोरारजी देसाई ऐसे व्यक्ति न थे। फलस्वरूप दलों के बीच तीखे क्षेत्रीय राजनीतिक अन्तर्विरोधों के गहराने के चलते, जिनके लिए मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चरण सिंह और जनसंघ घटक प्रमुख रूप से जिम्मेदार थे, जनता पार्टी टूट गयी और इस प्रकार राष्ट्र की आशाएं भी झुठला गयीं।

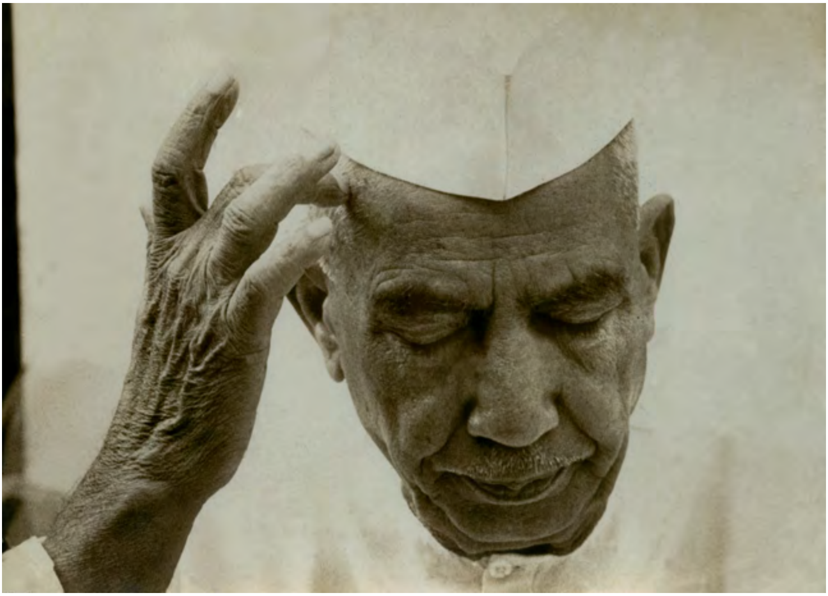

चरण सिंह, 1982

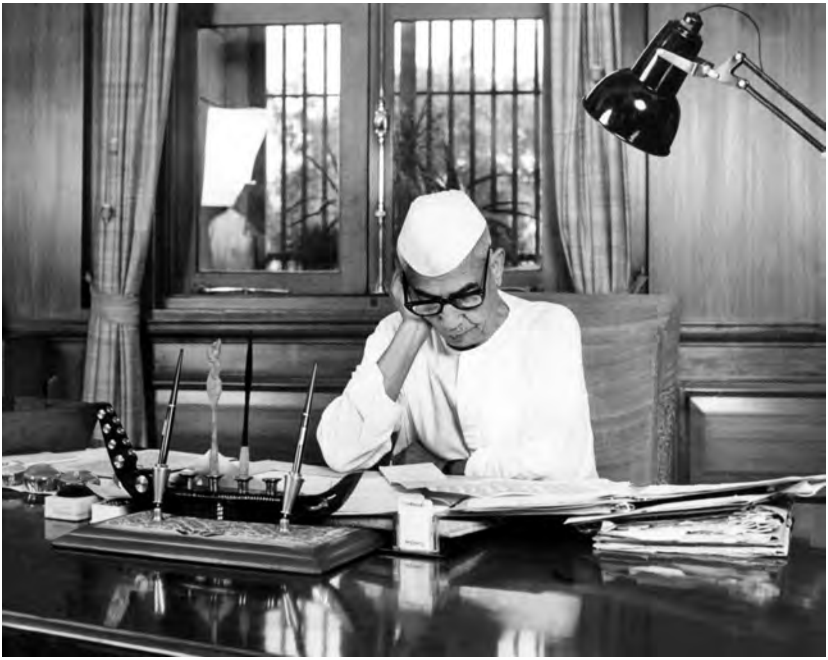

भारत के प्रधानमंत्री, 1979

भारत के प्रधानमंत्री

जनता सरकार के विखंडन के बाद चरण सिंह 28 जुलाई 1979 को एक विषम गठबंधन, जिसे अल्पकालिक होना ही था, के प्रमुख होने के कारण भारत के पांचवे प्रधानमंत्री बने। उनकी सरकार को बाहर से इंदिरा कांग्रेस का बिना किसी शर्त के समर्थन प्राप्त था, जिसने कुछ ही सप्ताह में अपना समर्थन वापस ले लिया, क्योंकि आपातकाल में की गयी ज्यादतियों के लिए संजय गांधी के विरुद्ध अदालतों में दायर वैधानिक मुकदमों को चरण सिंह ने वापस लेने से इंकार कर दिया। इससे पहले कि चरण सिंह को सदन का सामना करने का अवसर प्राप्त होता, उनकी सरकार गिर गई और तत्कालीन राष्ट्रपति एन. संजीवा रेड्डी द्वारा उन्हें 14 जनवरी 1980 को मध्यावधि चुनाव के नतीजे आने तक कामचलाऊ प्रधानमंत्री बने रहने को कहा गया।

प्रधानमंत्री रहते हुए चरण सिंह ने ग्राम विकास विभाग के स्तर को बढ़ाकर अगस्त 1979 में ग्रामीण पुनरुत्थान मंत्रालय बना दिया (1982 में इसका नाम ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया)।[xli] उनकी सरकार ने कृषि और कृषि उद्योग के अनेक क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं के लिए

स्वरोज़गार कार्यक्रम (TRYSEM) आरम्भ किया। "इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत हम 2 लाख ग्रामीण लड़के-लड़कियों में प्रत्येक वर्ष "करो और सीखो'' की तकनीक के द्वारा प्रासंगिक क्षमताओं का विकास करना चाहते हैं और ग्रामीण सेवा तथा कृषक विकास के सन्दर्भ में अन्य कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त कोष उपलब्ध कराना चाहते हैं।''[xlii]

उन्होंने सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों (हिन्दू-मुस्लिम दोनों) को 25 प्रतिशत आरक्षण देना, पदोन्नतियों में आरक्षण के सिद्धांत को समाप्त करना और उन लोगों के बच्चों को आरक्षण से बाहर करना - जिन्होंने आरक्षण के आधार पर नौकरी पाई हो या जो आयकर की सीमा में आते हों - प्रस्तावित किया। हालांकि भारत के राष्ट्रपति संजीवा रेड्डी ने उनके इस प्रस्ताव को चुनाव के बाद तक निलंबित रखने के लिए कहा।[xliii]

जनवरी 1980 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी और कांग्रेस पुनः सत्ता पर काबिज हो गयीं और उनकी वापसी के लिए जनता पार्टी खुद जिम्मेदार थी। चरण सिंह इस चुनाव में लोकसभा के लिए पुनः चुन लिये गये और उनकी पार्टी 41 सीट जीत कर लोकसभा में कांग्रेस के बाद दूसरे सबसे बड़े दल के रूप में स्थापित हुई। 1980 और 84 के दौरान वह राजनीतिक रूप से सक्रिय रहे और राष्ट्रीय महत्व के अनेक मुद्दों पर अपनी बात रखी। उदाहरण के लिए उन्होंने पंजाब में सिक्ख वर्ग के अतिवादी समुदाय की कार्यवाहियों के खिलाफ लिखा भी और बोला भी तथा भिण्डरावाले जैसे सशस्त्र सिक्ख अतिवादियों की कार्यवाहियों से निपटने के कांग्रेसी तौर-तरीकों को उन्होंने घुटने टेक देने जैसा कमजोर माना। उन्होंने खालिस्तान (सिक्खों के लिए एक अलग देश, जो भारत से काटकर बनाया जाता) की मांग का खुलेआम विरोध किया। इसके लिए उन्हें कई बार हत्या की धमकियां भी मिलीं, पर उन्होंने कोई परवाह नहीं की।

1984 के लोकसभा चुनावों में वह फिर से इंदिरा कांग्रेस की बढ़ती अलोकप्रियता से लड़ने के लिए राष्ट्रीय विपक्षी एकता के केन्द्र बने, किन्तु अक्टूबर 1984 में सिक्ख अंगरक्षकों द्वारा इंदिरा गांधी की कायराना हत्या के फलस्वरूप पैदा हुई सहानुभूति की लहर में इंदिरा के पुत्र राजीव गांधी ने दिसम्बर 1984 में लोकसभा चुनाव में अभूतपूर्व बहुमत से विजय प्राप्त की। चरण सिंह उन कुछेक विपक्षी नेताओं में से एक थे, जो 1984 में पुनः चुने गये, लेकिन इसके बाद उन्होंने कोई शासकीय पद ग्रहण नहीं किया।

नवम्बर 1985 में उन्हें भीषण मस्तिष्क-आघात हुआ। 29 मई 1987 को नई दिल्ली में उनका देहांत हो गया और वे अपने प्रेरणास्त्रोत महात्मा गांधी की समाधि के निकट स्थित 'किसान घाट' पर पंचतत्व में विलीन होकर अमर हो गये।

चरण सिंह द्वारा लिखित पुस्तकें, 1947-1986

चरण सिंह की बौद्धिक विरासत

चरण सिंह प्रबुद्ध क्षमतावान बिरले राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखीं और ऐसे अनेकों राजनीतिक प्रपत्र एवं राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र जारी किये जिनसे भारत के परिष्कृत एवं सुसंगत वैकल्पिक विकास की रणनीति का पता चलता है। उन्होंने पूंजीगत औद्योगीकरण, जिसका समर्थन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी तथा 1947 से आज़ादी के बाद से अब तक प्रत्येक सरकार ने किया था, के मुकाबले कृषि ग्रामों श्रमसाध्य कुटीर एवं लघु उद्योगों पर ज्यादा जोर दिया। उनके विचार वैश्विक विकास के चिंतकों; माइकल लिप्टन, ई.एफ. शूमेखर से दशकों आगे हैं और सुसंगत आंकड़ों से पुष्ट एवं पूर्णतः विवेचित हैं। वह असाधरण थे... 1947 और 1986 के बीच पर्याप्त मात्रा में जारी लिखित सामग्री तैयार करने में, जिसमें ग्रामीण भारत की प्रकृति और ग्रामीण भारत के लिए विकास की जो सही राह थी, आदि के दृष्टिकोण से, उनके पर्याप्त विस्तृत विचारों का उल्लेख मिलता है। वह विशुद्ध रूप से परिणाम देने वाले बौद्धिक थे, जिन्होंने अपने लेखों में विश्लेषण और समस्या के उपचार का शक्तिशाली मिश्रण प्रस्तुत किया। ... तीसरे, बौद्धिकता एवं

विचारों के सम्प्रेषण के साथ राजनैतिक कार्यवाही की क्षमता में वे सुस्पष्ट थे।"[xliv]

चरण सिंह द्वारा लिखी गयी महत्वपूर्ण पुस्तकों में, जो कृषि, छोटे काश्तकार, लघु उद्योग के समर्थन में भारत के लिए अधिकाधिक समतामूलक सामाजिक और आर्थिक विन्यास को तार्किक रूप से सम्बोधित हैं, प्रमुख हैं - 'एबोलिशन ऑफ जमींदारीः टू अल्टरनेटिव्स' (1947), 'एग्रेरियन रिवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश' (1957), 'ज्वाइंट फार्मिंग एक्स-रेडः दि प्रॉब्लम एण्ड इट्स सोल्यूशन' (1959), 'इंडिया'ज पॉवर्टी एण्ड इट्स सोल्यूशन' (1964), 'इंडिया'ज इकोनॉमिक पॉलिसीः दि गांधियन ब्लूप्रिंट' (1978), और 'इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडियाः इट्स कॉज एण्ड क्योर' (1981)।

ये सभी पुस्तकें अंग्रेज़ी भाषा में हैं, क्योंकि वह चाहते थे कि उनके विचार शहरी अभिजात्यों तक पहुंचें। इनमें से बहुत-सी पुस्तकों का हिन्दी अनुवाद हुआ, पर वह उस अनुवाद से नाखुश थे। हालांकि वह हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाये जाने का समर्थन करते थे परन्तु वह अंध-हिन्दीवादी नहीं थे।

इनमें से प्रत्येक पुस्तक 1920 से पोषित उनके विस्तृत एवं गहन अध्ययन का परिणाम थी, जिनमें वैश्विक और भारतीय परिदृश्य में आर्थिक विचारों, विकास-अध्ययनों, राज्य-हस्तक्षेप और इतिहास के बारे में उनकी प्रखर जानकारियां व्याख्यायित हैं।[xlv] यह सब इसलिए और भी अधिक प्रशंसनीय है क्योंकि वे शिक्षा के वातावरण से दूर एक अशिक्षित किसान के घर में पैदा हुए थे; और यह सच है कि ये सभी पुस्तकें उन्होंने राजनीतिक उठापटक के बीच लिखी थीं। 1960 में उत्तर प्रदेश की दलगत राजनीति से विक्षुब्धता के क्षणों में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में आने की अपनी इच्छा जाहिर की थी।[xlvi] उनके बच्चों और उनके नाती-पोतों की

मधुर स्मृति में चरण सिंह घर में हमेशा पढ़ते हुए या लिखते हुए व्याप्त हैं। 1977, 1980, 1984 की लोकसभाओं के सदस्य के लिए उनके अधिकारिक प्रोफाइल में उनकी पसंद और मनोरंजन 'पढ़ना' ही उल्लिखित है।

व्यक्ति की चारित्रिक पहचान के सन्दर्भ में चरण सिंह की सुदृढ़ धारणायें थीं और उन्होंने स्वयं भी सादगी और संयम से भरा जीवन जिया। वह जीवनभर शाकाहारी रहे, न उन्होंने बीड़ी-सिगरेट पी, न ही शराब का सेवन किया। जो लोग ये काम करते थे, उनके प्रति वह पूर्वाग्रहीत रहे। उन्होंने यौनिक भ्रष्टाचार का, चाहे वह आदमी में हो या औरत में, कभी भी समर्थन नहीं किया और उनके नियमों में से एक नियम था - वैवाहिक जीवन में एक-दूसरे के प्रति ईमानदार रहना। सार्वजनिक क्षेत्र में व्यक्ति के निजी एवं लोक जीवन का आधार वह निजी तौर पर निष्कलंक होना, वित्तीय ईमानदारी एवं भौतिक वृत्तियाँ (उपभोक्तावाद के विरुद्ध) आदि को मानते थे। उन्होंने फिल्मी संगीत नहीं सुना, कभी सिनेमा-थियेटर नहीं गये और अपने परिवार-जनों के संग-साथ ही फुर्सत के क्षण बिताये। उनके जीवन और आदर्श में केवल भारत का विचार ही समाया हुआ था, अन्य किसी चीज का कोई अर्थ न था। उनकी कठोर नैतिकता अक्सर उनके संगी-साथियों और विरोधियों के लिए भी समस्या खड़ी कर देती थी। वह इस बात के लिए भी जाने जाते थे कि यदि वह अपने राजनीतिक दल के अभ्यार्थी को शराब पीने का आदी या भ्रष्ट पाते, तो वह मतदाताओं से उसके विरुद्ध वोट देने की अपील कर डालते थे।

एक सक्रिय राजनीतिज्ञ के रूप में चरण सिंह की प्रमुख विशेषताएं- उनकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा, है जिसे कभी भी चुनौती नहीं मिली, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार के विरुद्ध उनके द्वारा जीवनभर चलाये गये अभियान, उनके द्वारा किये गये अनथक कठोर श्रम और एक काबिल प्रशासक के रूप में उनका प्रभाव छोड़ना, आदि रहीं। चरण सिंह ने अपने

स्वतंत्र राजनीतिक संगठनों को अवाम से प्राप्त चन्दों के जरिये ही चलाया, जो कि किसी भी अन्य राजनीतिक दल के लिए सम्भव न था, और किसी भी परिस्थिति में धनी पूंजीपतियों के दान को स्वीकार न करने के घोषित सिद्धांत का पालन किया।[xlvii] उत्तर प्रदेश के प्रभावी औद्योगिक घरानों द्वारा प्रस्तावित सहयोग की बड़ी राशियों को उनके द्वारा अस्वीकार करने की कहानियां आम हैं।

चरण सिंह निर्विवाद रूप से एक महत्वाकांक्षी राजनीतिज्ञ थे। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में उन्होंने राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करना चाहा, लेकिन अपने परिवार या खुद के लिए नहीं, अपितु भारतीय समाज में ऐसे तत्वरूपी तथा मौलिक परिवर्तनों को लाने के लिए, जिनका उन्होंने विस्तारपूर्वक अपनी अनेकों पुस्तकों, प्रलेखों/प्रकाशनों और अपने से सम्बंधित राजनीतिक दलों के राजनीतिक घोषणा-पत्रों में व्याख्यायित किया। अक्सर वह राजनीतिक शक्ति पाना चाहते थे और पा भी जाते थे और फिर उसे उन क्षणों में छोड़ देते थे, जब प्रणालीगत परिवर्तनों को लाने की उनकी अपेक्षाओं और उनके सिद्धांतों के बीच संघर्ष अनुमान से भी ज्यादा बड़ा हो जाता था। अनेक अवसरों पर वे बहुधा व्यक्तियों की परख में जरूरत से ज्यादा अनुमानवादी हो जाते थे तो किसी समय बेहद कठोर और गैर-समझौतावादी।

चरण सिंह का राजनीतिक जीवन, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके अपने जिला मेरठ से सारे राज्य तक और अन्ततः राष्ट्रीय राजनीति तक, भारतीय राजनीतिक तंत्र के हर स्तर पर सक्रिय रहा। सत्ता-शिखर तक पहुंचने तक चरण सिंह भारत के छोटे और मझोले काश्तकारों के प्रमुख प्रवक्ता के रूप में पहचाने गये और बाद में 'पिछड़ी' किसान जातियों एवं ऊंची जातियों के बीच स्थित मध्यमार्गी सामाजिक स्तर की पिछड़ी कृषक जातियों की आकांक्षाओं में स्वयं को चिन्हित कर दिया। वे ग्रामीण भारत

की ऐसी आवाज़ हैं जिसे हम नहीं सुनते, जबकि आज के दौर में कृषि-संकट की कुलबुलाहट को हम साफ़ सुनते हैं।

चरण सिंह की राजनीतिक विरासत स्पष्टतः ग्रामीण भारत के पक्ष में निर्मित नीतियों, और भारत की भलाई में अन्तर्निहित है। राजनीतिक शक्ति को पाने और खोने की उठापटक के बीच, उन्होंने स्वयं या अपने परिवार को न लाभान्वित किया न होने दिया। उनका विश्वास था कि वह अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जिसे भारत के विकास की आधारभूत समस्याओं का पर्याप्त ज्ञान है। इनके सन्दर्भ में उनके समाधान जमीनी, चुनावी लोकतंत्र और स्वतंत्र उद्यम - एक लघु उद्यम, छोटी कृषि अर्थव्यवस्था - आधुनिक विश्व की लेखा-विधि पर आधारित थे। लेकिन इस समाधान में अर्थव्यवस्था के उत्पादक साधनों पर न तो निजी नियंत्रण की वकालत करने वाले पूंजीपतियों का और न ही राज्य कार्पोरेट नियंत्रण की वकालत करने वाले साम्यवादियों का समावेशन था। इसके बजाए भारत के कृषि-प्रधान विकास के हल के रूप में उन्होंने विशिष्ट मध्यमार्गी रास्ते को चुना, जो किसी भी विदेशी आदर्श की न तो नकल करता था और न ही उसका अनुकरण करता था, हालांकि वे उनके योगदान के प्रति पूर्णतः सजग थे।

अपने पूरे सार्वजनिक जीवन में गरीबी, बेरोज़गारी, असमानता, जातिवाद और भ्रष्टाचार - इन पॉच समस्याओं ने उनकी सोच और कार्यों को प्रभावित रखा। ये पॉचों समस्याएं आज भी भारत में मौजूद हैं और उनके दिये समाधान आज भी हालात में सुधार और समस्याओं के अंतिम उन्मूलन हेतु जीवंत और प्रासंगिक हैं।

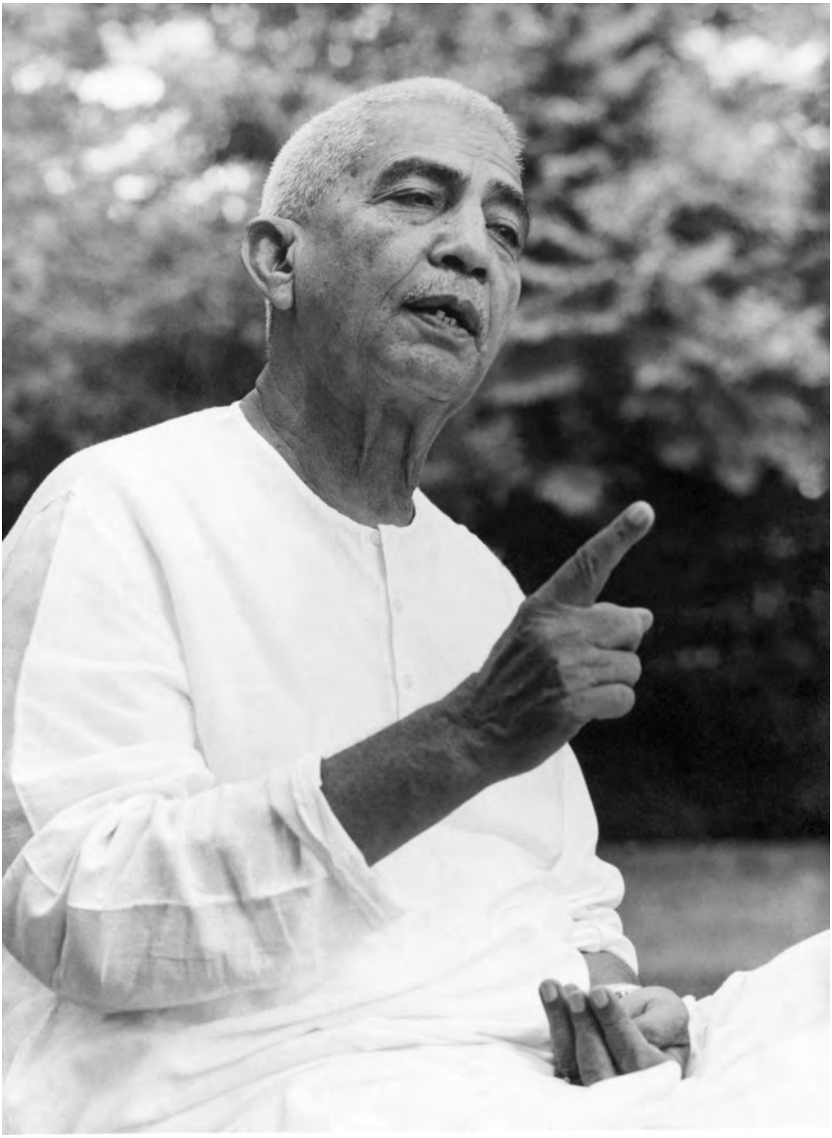

चरण सिंह, दिल्ली, 1984

जीवन का कालक्रम

1898: बुलंदशहर ज़िले के ग्राम भटौना से बादाम सिंह के 18 वर्षीय पुत्र मीर सिंह का बुलंदशहर के ही गांव चितसौना अलीपुर की नेत्र कौर के साथ विवाह। मीर सिंह कुचेसर के जमींदार (भूस्वामी) के स्वामित्व वाली नूरपुर गांव में पॉच एकड़ जमीन के जोतदार,

- एक भूमिहीन किसान थे। उनके पांच बच्चों में सबसे बड़े **चरण सिंह का जन्म आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के नूरपुर गांव में 23 दिसम्बर 1902 को हुआ।**

1903: मीर सिंह मेरठ जिले में 60 किलोमीटर उत्तर, भूपगढ़ी में आ बसे, जहां उनका परिवार 1922 तक रहा।

- चरण सिंह ने प्राथमिक शिक्षा चौथी कक्षा तक एक किलोमीटर दूर जानी खुर्द गांव में प्राप्त की,और कुछ परीक्षाएं पॉच किलोमीटर दूर सिवाल गांव में दीं।

1913-1919: चरण सिंह ने स्कूली शिक्षा 15 किलोमीटर दूर मेरठ शहर में प्राप्त की ।

- **1913:** मॉरल ट्रेनिंग स्कूल के प्राइवेट बोर्डिंग में चले गये, सबसे बड़े चाचा लखपत सिंह ने उनकी शिक्षा का खर्च वहन करने का वादा किया।
- **1914:** मेरठ गवर्नमेंट हाई स्कूल में छठी कक्षा में प्रवेश लिया। 9 वीं कक्षा से विज्ञान विषय लिया, शुरुआत में ही अंग्रेजी, अर्थशास्त्र और इतिहास में विशेष योग्यता दिखाई। यहीं से मैट्रिक्यूलेशन (कक्षा 10) उत्तीर्ण की।

1919-1923: आगरा कालेज, आगरा में विज्ञान स्नातक का अध्ययन।

- विज्ञान विषय सहित इन्टरमीडिएट (कक्षा 12) में अध्ययन।
- मेरठ के प्रतिष्ठित डॉक्टर भोपाल सिंह द्वारा, जो प्रतिभाशाली और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों की मदद करते थे, 10 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति।
- खिलाफत और असहयोग आन्दोलन के दौरान गांधी जी के आह्वान पर कॉलेज शिक्षा के बायकॉट करने का निश्चय किया, किन्तु बाद में बड़ों के समझाने पर शिक्षा पूरी करने को राजी हुए।
- **1921:** 'यंग इंडिया' में लिखे गांधी जी के लेखों से प्रेरित होकर जाति की कट्टरता पर हमला बोला, युवा चरण सिंह ने अपने हॉस्टल के वाल्मीकि (सफाईकर्मी) द्वारा तैयार तथा परोसा गया भोजन खाया। हॉस्टल के साथियों द्वारा उनका बहिष्कार किया गया और हॉस्टल की रसोई में खाना खाने से उन्हें मना कर दिया गया, पर वे अटल रहे।
- **1922:** रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की परीक्षा में शामिल हुए और सफल रहे, किन्तु ड्रॉइंग में निम्नतम अंकों से भी कम अंक प्राप्त करने पर प्रवेश पाने योग्य नहीं समझे गये। यहां शैक्षिक असफलता से उनका पहला सामना हुआ। इस अनुभव ने भविष्य के लिए उन्हें सिखाया कि हर विषय पर, वह चाहे कितना भी अमहत्वपूर्ण दिखे, पूरा ध्यान देना चाहिए।
- **1922:** मीर सिंह मेरठ जिले से भदौला गांव आ गये, जहां उन्होंने कुछ जमीन खरीदी और जीवन के अन्त तक रहे।

1923-1925: आगरा कालेज से इतिहास में स्नातकोत्तर अध्ययन।

- ब्रिटेन, फ्रांस और भारत के इतिहास का अध्ययन।
- **25 जून 1925:** संयुक्त पंजाब, रोहतक जिले के ग्राम गढ़ी कुण्डल की गायत्री देवी से विवाह। जालंधर के कन्या महाविद्यालय से हाई स्कूल पास, गायत्री देवी का सम्बंध एक आर्यसमाजी परिवार से था।

1927: मेरठ कालेज, मेरठ (जो उस समय आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध था) से कानून (एल.एल.बी.) की डिग्री हासिल की।

- उनके सिद्धातों ने उनके चरित्र और कार्यों को एक दिशा दी। इस मूल सामाजिक विश्वास को दृढ़ किया कि हिन्दू समाज में व्याप्त जातीय विभाजन तमाम दोषों का मूलभूत कारण है।
- चौधरी साहब ने बड़ौत जाट हाई स्कूल, मेरठ और लखावटी जाट डिग्री कालेज, बुलंदशहर में प्रधानाचार्य का पद तब तक स्वीकार करने से इंकार कर दिया, जब तक कि उनके नाम के आगे जुड़ा जाति-सूचक 'जाट' शब्द नहीं हटाया जाता, जिसे

प्रबंधकों ने नहीं हटाया। सामाजिक जीवन में जातिगत अभिमान के प्रति निष्ठा का विरोध किया।

- उनकी सबसे बड़ी संतान सत्या का जन्म 14 सितम्बर 1927 को हुआ।

1928: मेरठ जिले के गाजियाबाद में वकालत (सिविल) की प्रैक्टिस शुरू की, जिसे 1939 तक जारी रखा।

- उनकी तीक्ष्ण बुद्धि, तर्क-क्षमता, दूसरों को प्रभावित करने की योग्यता, मामले की गहराई तक जाने की प्रवृत्ति, कठिन परिश्रम और गरीबों के प्रति सहानुभूति ने उनकी वकालत को नई ऊँचाइयां दीं। उनका प्रयास होता था कोर्ट (न्यायालय) में जाये बिना ही विरोधी पक्षों के बीच समझौता करा देना।

1929: 27 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने और 1967 तक रहे।

- गाजियाबाद शहर कांग्रेस कमेटी की स्थापना की, जिसमें कि वह 1939 तक विभिन्न चयनित पदों पर रहे।

1930: मेरठ जिले में आर्यसमाज और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय रहे।

- यहीं दयानन्द सरस्वती के धार्मिक विचारों से परिचय हुआ और मोहनदास गांधी की राजनीतिक एवं आर्थिक विचारधारा से प्रभावित हुए।
- **1930 -1939:** गाजियाबाद आर्यसमाज समिति के अध्यक्ष या महासचिव रहे।
- **5 अप्रैल 1930:** गांधी जी का नागरिक अवज्ञा आन्दोलन शुरू होने पर नमक सत्याग्रह में भाग लिया और पहली बार छह महीनों के लिए अंग्रेजों की जेल में भेजे गये। उनकी पत्नी गायत्री देवी ने घर-परिवार चलाने के लिए अपनी एकमात्र सोने की चूंड़ियां बेच दीं और अध्यापिका की नौकरी छोड़कर गाजियाबाद से गांव चली गयीं।
    - 17 सितम्बर 1930 को उनकी दूसरी बेटी वेद का जन्म हुआ।

जनवरी 1931: मेरठ जिला बोर्ड के चुनावों में निर्विरोध चुने गये। चौधरी खुशीराम (अध्यक्ष) और मौलवी वशीर अहमद (वरिष्ठ उपाध्यक्ष) के साथ मिलकर 1935 तक उपाध्यक्ष रहे।

- **1932:** 'कम्युनल अवार्ड' के विरोध में गाजियाबाद में कांग्रेस आन्दोलन का नेतृत्व किया। कांग्रेस ने अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष, , जो दोनों जेल में थे, की अनुपस्थिति में उन्हें जेल से बाहर रहने और पार्टी का कामकाज देखने का निर्देश दिया।

- ग्रामीण क्षेत्रों की व्यापक यात्राएं कीं, मेरठ के ग्रामांचल में व्याप्त गरीबी का खुलासा और सामाजिक बुराईयों से उनका आमना-सामना हुआ। इन सबके चलते उनमें यह आश्वस्ति पैदा हुई कि राष्ट्र की उन्नति एवं इन बुराईयों से मुक्ति के लिए अंग्रेजी राज की समाप्ति पहला कदम है।
    - गाजियाबाद नगरपालिका के एक शोषक कर्मचारी के पंजों से एक विधवा और उसकी युवा पुत्री को छुटकारा दिलाया, बेटी का विवाह सम्पन्न कराया तथा मां को सहारा दिलाने में मदद की।
    - रईसपुर गांव में एक बूढ़े दुकानदार से एक अल्पवयस्क बालिका की शादी रुकवाने में असफल रहे, बेहद गरीबी के चलते पिता द्वारा कम उम्र पुत्री के विवाह की इस घटना ने उनके मन पर अमिट छाप छोड़ी और जीवन में लम्बे समय तक उनके मानस पटल पर अंकित रही।
    - अंग्रेजी भाषा को अंग्रेजों के दमनकारी शासन के रूप में देखा और एक मजिस्ट्रेट के विरोध के बावजूद अपने कुछ मुकदमों में पैरवी की भाषा के रूप में हिन्दी का प्रयोग किया। भारत की राष्ट्रीय एवं सूत्र भाषा के रूप में हिन्दी के सक्रिय समर्थक बने।
- परिषद के एक कनिष्ठ कर्मचारी द्वारा उनके निरीक्षण-यात्रा के लिए तैयार किये गये झूठे यात्रा-बिलों को वापस कर दिया और निजी कार्यों के लिए बोर्ड से चपरासी लेना अस्वीकार कर दिया। उन्होंने शुचिता के ऐसे व्यक्तिगत उदाहरण स्थापित किये, जिनसे आने वाले दिनों में सरकारी पदों पर रहते हुए ईमानदारी के मानदंडों को सार्वजनिक रूप से परिभाषित किया गया।
- **1932:** जातिवाद के विरुद्ध अपने विचारों को अभिव्यक्ति देने के लिए एक *हरिजन* (तब दलितों को यही कहा जाता था) को रसोईया रखा, जो उनके साथ 1939 तक रहा।
    - 23 सितम्बर को तीसरी संतान ज्ञान का जन्म हुआ।

25 फरवरी 1937: 34 वर्ष की आयु में संयुक्त प्रांत विधान सभा के सीमित निर्वाचन क्षेत्र से दिसम्बर 1936 में मेरठ जिले (दक्षिण-पश्चिम), जिसमें बागपत और गाजियाबाद तहसील शामिल थीं, से कांग्रेस के टिकट पर चुने गये (उस समय मेरठ, मुजफ्फरनगर और मथुरा जिले दिल्ली जिला कांग्रेस के हिस्से थे)।

- ***जमींदारों की नेशनल एग्रीकल्चरिस्ट पार्टी*** के प्रत्याशी को हरा कर 78.06 प्रतिशत मत प्राप्त किये।
- छपरौली विधान सभा क्षेत्र से लगातार आठ बार चुने गयेः 1937, 1946, 1952, 1957, 1962, 1967, 1969 और 1974।
    - 23 फरवरी 1937 को चौथी संतान सरोज का जन्म हुआ।

17 जुलाई 1937 से 2 नवम्बर 1939: विधान सभा में बहुमुखी ग्रामीण और किसान-समर्थक कानून और कांग्रेस विधान मंडल दल में प्रगतिशील प्रस्ताव तैयार किये तथा पेश किये। राज्य कांग्रेस नेतृत्व की नजरों में जगह बनाई।

प्रशासन और पुलिस के कमजोर कार्य-प्रदर्शन के चलते कांग्रेस विधान मंडल दल की बैठक बुलाने और उसमें विचार-विमर्श करने का प्रस्ताव। गोविन्द बल्लभ पंत और जवाहरलाल नेहरू की प्रतिक्रिया से निराश।

- **नवम्बर 1938:** चरण सिंह ने काकोरी षडयंत्र काण्ड से प्रसिद्ध हुए विष्णु शरण दुबलिश के अंडमान जेल से 10 वर्ष की सजा काटकर लौटने के अवसर पर उनके सम्मान में गाजियाबाद में एक विशाल जनसभा आयोजित की। वे जीवनभर के लिए मित्र और राजनीतिक सहयोगी बन गये, और आगे उन्होंने मेरठ में चरण सिंह का राजनीतिक आधार मजबूत किया।
- **1938:** शोषणकारी अनाज विक्रेताओं एवं व्यापारियों के विरुद्ध अन्न उत्पादकों के हितों को सुरक्षित बनाने की दृष्टि से एक प्राइवेट बिल के रूप में *'कृषि उत्पाद विपणन बिल'* का मसौदा पेश किया। चरण सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गये बिल के मसौदे पर आधारित 1940 में सर छोटूराम के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने मंडी समिति कानून पारित किया। उत्तर प्रदेश में इस बिल को पारित होने के लिए, 1964 में चौधरी साहब के कृषि मंत्री बनने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी।
- 31 मार्च 1939 और 1 अप्रैल 1939 को 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में एवं लखनऊ में, कृषि उत्पादकों के संरक्षण हेतु विधायी उपायों पर आधारित लेख प्रकाशित हुए। अंग्रेजी में लिखे, तार्किक रूप से प्रस्तुत, आंकड़ों (डाटा) पर आधारित यह लेख उनके सार्वजनिक जीवन के दौरान समाचार-पत्रों में किये गये विस्तृत लेखन के अग्रगामी ध्वजवाहक हैं।
- **अप्रैल 1939:** सभी पट्टेदारों या वास्तविक जोतदारों को वार्षिक लगान का दस गुना एकमुश्त जमा करने पर, जिस जमीन पर वे खेती करते थे, उसका मालिकाना हक देने के लिए 'लैण्ड यूटिलाइजेशन बिल' तैयार किया। इस बिल का *जमींदारों* द्वारा कड़ा विरोध हुआ और इसे विधान सभा में नहीं रखा जा सका।
- **5 अप्रैल 1939:** कांग्रेस विधान मंडल दल की कार्यकारिणी के समक्ष इस आशय का प्रस्ताव रखा कि सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों में 50 प्रतिशत स्थान खेतिहरों की संतानों और उनके आश्रितों के लिए आरक्षित रखे जायें।
- **अप्रैल 1939:** कांग्रेस विधान मंडल दल के सम्मुख इस आशय का प्रस्ताव रखा कि अनुसूचित जाति के मामलों को छोड़कर, शिक्षण संस्थानों या सरकारी

नौकरियों में प्रवेश के समय किसी भी हिन्दू से उसकी जाति के बारे में न पूछा जाये। पार्टी ने इस प्रस्ताव पर विचार भी नहीं किया।

- **1939:** 'संयुक्त प्रांत कृषक एवं खेतिहर ऋण-मुक्ति विधेयक' तैयार करने में प्रमुख भूमिका अदा की, जिससे उत्तर प्रदेश के बहुत से किसान सूदखोरों के कर्ज के फंदे से मुक्ति पा सके और उनके खेत नीलाम होने से बच गये। उत्तर प्रदेश काश्तकारी अधिनियम- 1939 (यू.पी. टेनेंसी एक्ट-1939) के अन्तर्गत किसानों को राहत देने के लिए राजस्व मंत्री से बात की।
- कांग्रेस विधान मंडल दल की बैठक की मांग की, जिसमें उन्होंने आम जनता की जरूरतों के प्रति अंग्रेज प्रशासन की उत्तरदायित्वहीनता और पुलिस प्रशासन की उदासीनता के खिलाफ आवाज उठाई।
  - द्वितीय विश्वयुद्ध में ब्रिटेन ने इकतरफा तौर पर भारत की सहभागिता की घोषणा कर दी। विरोध में सभी कांग्रेसी राज्य सरकारों ने इस्तीफे दे दिये।

दिसम्बर 1939: कांग्रेस सरकार के इस्तीफे के बाद **गाजियाबाद से मेरठ शहर चले आये।**

- 1939 से 1946: मेरठ जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष या महासचिव रहे।
- मेरठ जिले के सम्माननीय प्रमुख कांग्रेसी नेता और बड़े जमींदार रघुवीर नारायण सिंह के जन्मजात विशेषाधिकार से व्यक्तिगत क्षमता को, नेतृत्व का महत्वपूर्ण हस्तांतरण हुआ।
  - 12 फरवरी 1939 को पाँचवीं संतान अजित का जन्म हुआ।

नवम्बर 1940-अक्टूबर 1941: 'व्यक्तिगत सत्याग्रह' आन्दोलन के दौरान दूसरी बार बरेली जेल भेजे गये।

- प्रारम्भ में मेरठ जेल में रखे गये और बाद में बरेली जेल भेजे गये। वहां उन्होंने लगातार अध्ययन किया और जेल डायरियां लिखीं, जिनमें जॉन स्ट्रेसी की 'दि थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस ऑफ सोशलिज्म', एडगर स्नो की 'रेड स्टार ओवर चाइना', सिडनी और बिट्राइस वेव की 'सोवियत कम्युनिज्म', एमिल बर्न्स की 'ए हैण्ड बुक ऑफ मार्क्सिज़्म, जी.डी.एस. कोले की 'प्रैक्टिकल इकोनॉमिक्स' जैसी किताबों से बड़े पैमाने पर लिये गये अंश उद्धृत हैं। यूरोपियन, इंग्लिश, रशियन और भारतीय कृषि पर विस्तृत रिपोर्ट्स का अध्ययन किया।
- भारतीय परम्पराओं और आचार-विचार पर जेल से अपने बच्चों को पत्राचार के रूप में प्रेषित हिन्दी में *'शिष्टाचार'* पुस्तक लिखी। किसी को क्षति न पहुंचाने वाली इस पाण्डुलिपि को पुलिस ने जब्त कर लिया और उन्हें सालों बाद

लौटाया। इस बीच उनका परिवार बेहद परेशानियों के बीच गांव में इधर-उधर रहा।

23 अक्टूबर 1942-नवम्बर 1943: भारत छोड़ो आन्दोलन के दौरान 13 महीने के लिए तीसरी जेल यात्रा

- जेल जाने से पूर्व गाजियाबाद, हापुड़, मवाना, सरधना और बुलंदशहर में औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध ढाई महीने तक भूमिगत संघर्ष चलाया। पुलिस ने 'देखते ही गोली मार देने' का आदेश जारी किया, उन्होंने स्वैच्छिक रूप से समर्पण कर दिया। जेल से छूटने पर वापस सिविल लॉ की प्रैक्टिस शुरू कर दी। एक कठिनाइयों भरा जीवन जिया।
  - छठी एवं अंतिम संतान, शारदा का जन्म 23 दिसम्बर 1942 को हुआ।

नवम्बर 1945: प्रशासन को अधिकाधिक प्रतिनिधि मूलक और उत्तरदायी बनाने की दृष्टि से सरकारी सेवाओं में किसानों को, जो संयुक्त प्रांत की ग्रामीण जनसंख्या में 85% थे, नौकरी देने का प्रस्ताव रखा।

- चरण सिंह ने 9 सितम्बर 1945 को भूमि और कृषि पर एक कांग्रेस घोषणा-पत्र का मसौदा तैयार किया, जिसमें जमींदारी उन्मूलन की बात की गयी। नवम्बर 1945 में आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में बनारस में हुई किसानों की सभा में इसे अंगीकार किया गया। और यही मसौदा दिसम्बर 1945 में ऑल इंडिया कांग्रेस वर्किंग कमेटी द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव का आधार बना।

21 मार्च 1946-12 मई 1948: चरण सिंह संयुक्त प्रांत विधान सभा के लिए मेरठ जिले (दक्षिण-पश्चिम) से दूसरी बार चुने गये और यू.पी. कांग्रेस मंत्रिमंडल में संसदीय सचिव (कनिष्ठ मंत्री) नियुक्त किये गये।

- 24 अप्रैल 1946-सितम्बर 1947: राजस्व मंत्री हुकुम सिंह के संसदीय सचिव।
  - यह सुनिश्चित किया कि राजस्व सम्बंधी अभिलेखों में अनुसूचित जाति के अलावा अन्य पट्टाधारकों की जाति दर्ज नहीं की जायेगी।
- भूमि सुधार नियमावली में एक नया अनुच्छेद शामिल किया, जिसके तहत जनहित उद्देश्यों के लिए आधे मील के अन्दर उपलब्ध ऊसर या अनुपयोगी जमीन के होते हुए कृषि भूमि के अधिग्रहण का निषेध किया गया।
- **सितम्बर 1947 की शुरूआत - 12 मई 1948:** स्थानीय निकाय एवं स्वास्थ्य मंत्री आत्माराम गोविन्दराम खेर के निजी सचिव। चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य विभागों का स्वतंत्र प्रभार मिला।

14 नवम्बर 1946-3 जुलाई 1948: कांग्रेस की जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार समिति (जेड.ए.एल.आर.सी.) के सदस्य, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन का जिम्मा सौंपा गया।

- **जेड.ए.एल.आर.सी. ने 'संयुक्त प्रांत जमींदारी उन्मूलन समिति' की रिपोर्ट प्रकाशित की।** सुपरिन्टेंडेन्ट, प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, इलाहाबाद, यू.पी.। पृष्ठ 611।
- **1 सितम्बर 1946:** जबकि जेड.ए.एल.आर.सी. विवेचना कर रही थी, जोतदारों से, जिस जमीन को वे जोतते थे, खाली कराने से रोकने के लिए यू.पी. टेनेन्सी एक्ट में सुधार सुनिश्चित किया और 1 जनवरी 1940 तक, जिनसे भूमि खाली करवा ली गयी थी, उन्हें बहाल किया गया।
- **12 जनवरी 1948:** सभी जोतदारों को उस जमीन पर, जिस पर उनकी झोपड़ी बनी थी, उत्तर प्रदेश विलेज आबादी एक्ट के तौर पर उनके हस्तांतरण का अधिकार सुनिश्चित किया गया। यह सभी किसानों, विशेषकर अनुसूचित जातियों के लिए एक वरदान था, क्योंकि यह कानून जमीन खाली कराने से जमींदारों को बाधित करता था।
- **1946:** उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 1967 तक सदस्य।
- **1946 से:** उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधान मंडल दल के महासचिव। 1956 में तत्कालीन मुख्यमंत्री सम्पूर्णानन्द से मतभेदों के चलते इस्तीफा।
- **21 मार्च 1947:** कांग्रेस विधान मंडल दल के सम्मुख किसान संतानों को सरकारी नौकरियों में 60% आरक्षण देने हेतु एक उत्साही और सुगठित प्रस्ताव रखा।
    - **1947:** ***'हाउ टू एबोलिश जमींदारीः व्हिच आल्टरनेटिव सिस्टम टू एडॉप्ट'* पुस्तिका का 1947 में प्रकाशन।** इलाहाबादः सुपरिन्टेंडेन्ट, प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, संयुक्त प्रांत।
    - **1947: पहली पुस्तक 'एबोलिशन ऑफ जमींदारीः टू ऑल्टरनेटिव्स' का प्रकाशन।** किताबिस्तान, इलाहाबाद, यू.पी. पृष्ठ 263

13 मई 1948 - 3 जून 1951: संयुक्त प्रांत (बाद में उत्तर प्रदेश) के प्रीमियर (बाद में मुख्यमंत्री) गोविन्द बल्लभ पंत के संसदीय सचिव

- न्याय एवं विधि विभाग के संसदीय सचिव, जमींदारी उन्मूलन पब्लिसिटी बोर्ड और जमींदारी उन्मूलन कोष का भी प्रभार।
    - 1946: 1967 तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (ए.आई.सी.सी.) के सदस्य रहे।

- राज्य प्रशासन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रीमियर पंत को अनेक बार त्याग-पत्र प्रस्तुत किया (उदाहरणः बुलंदशहर में रामगढ़ कोर्ट ऑफ वाड्र्स का घोटाला), वरिष्ठ मंत्रिमंडलीय साथियों के कार्य में गुणवत्ता एवं सामर्थ्य में कमी तथा चरण सिंह ने उन्हें अपनी अपेक्षा कम सक्षम पाया। पंत, जो एक शांत और समावेशी व्यक्ति थे, ने इस्तीफों के प्रस्ताव अस्वीकार कर दिये, चरण सिंह के असंतोष को शांत किया और उनकी ऊर्जा को भविष्य में ऐतिहासिक कार्यों को सम्पन्न करने की दिशा दी।
- **1948-1951: जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार विधेयक (जेड.ए.एल.आर.)** का प्रतिपादन किया, इसे उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की प्रमुख उपलब्धि माना।
  - **18 अक्टूबर 1948:** जमींदारी उन्मूलन की अंतिम अनुशंसाओं का विरोध करते हुए 18 पृष्ठ का एक बेहद तार्किक नोट पंत को सौंपा, जमींदारी उन्मूलन विधेयक तैयार करनेवाली राजस्व एवं कानून अधिकारियों की मसौदा समिति का प्रभार सौंपा गया और उन्होंने इसे कानून का रूप दिया।
  - **12-17 मई 1949:** मसौदा समिति द्वारा सौंपे गये विधेयक का उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने अनुमोदन किया।
  - **7 जुलाई 1949:** विधेयक विधानसभा की संयुक्त प्रवर समिति को प्रस्तुत किया गया, जिसने 9 जनवरी 1950 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
  - **24 जनवरी 1951:** विधेयक दोनों सदनों द्वारा पारित हो गया, और भारत के राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया।
- **12 जून 1950:** सूचना निदेशालय के साथ ही प्रीमियर (मुख्यमंत्री) के संसदीय सचिव का दायित्व सौंपा गया।
  - **1951:** राज्य चुनाव समिति या कांग्रेस संसदीय बोर्ड के सदस्य। वह कटु गुटीय राजनीति का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, किन्तु पार्टी में अपना अस्तित्व बचाये रखने को उन्हें इसमें भाग लेना पड़ा। 1965 में इस्तीफा दे दिया।
  - **फरवरी 1951:** प्रदेश कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी की बैठक में पर्याप्त बहुमत के साथ एक प्रस्ताव रखा कि पार्टी के किसी भी सक्रिय सदस्य को जातीय संस्थाओं या संगठनों से सम्बद्ध होने की अनुमति न दी जाये।**4 जून-8 अगस्त 1951: न्याय एवं सूचना मंत्री**

9 अगस्त 1951-19 मई 1952: कृषि, पशुपालन और सूचना मंत्री

20 मई 1952-27 दिसम्बर 1954: राजस्व, अल्पता, कृषि, गन्ना विकास, खाद्यान्न विकास और पशु-पालन मंत्री

- **1 जुलाई 1952: उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून का क्रियान्वयन शुरू किया।** चरण सिंह और समर्पित नौकरशाहों की टीम द्वारा बारीकी और सतर्कतापूर्वक तैयार किये गये मसौदे के चलते इस कानून के किसी भी हिस्से को न्यायालय में सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दी जा सकी। 1952 में एक ऐसे प्रदेश में, जहां 85 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर थी, खेतिहर किसान और राज्य के बीच से बिचौलिये जमींदारों को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। इन जमींदारों और ताल्लुकेदारों (भूस्वामियों) की मध्यस्थहीनता के कारण इन भूमिहीन बटाईदारों को सीरदार या अधिवासी का स्वतंत्र, आत्मनिर्भर दर्जा प्राप्त हुआ।
- जेड.ए.एल.आर. ने हर ग्रामवासी को उसके घर, कुएँ और पेड़ों का स्वामी बना दिया। यह कानून भूमिहीन अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए विशेष रूप से लाभकारी था, जो तब तक पूरी तरह जमींदार की दया पर निर्भर थे। जेड.ए.एल.आर. एवं समेकित (चकबंदी) कानून के तहत आबादी क्षेत्र में भूमि आवंटन में भूमिहीनों को वरीयता दी गई।
- नये कानून के तहत ग्रामीणों को प्राप्त उनके अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ से भाषणों का एक जोरदार कार्यक्रम चलाया, सुगठित तर्कों से सज्जित हिन्दी और अंग्रेजी में समाचार-पत्रों में आलेख, पैम्फलेट्स प्रकाशित कराये और 1952 से 1957 के बीच पूरे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों विशाल जनसभाएँ कीं।
- **1953: उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम को सूत्रबद्ध और निर्देशित करने का रास्ता तैयार किया।** व्यक्तिगत रूप से किसानों के बिखरे खेतों को एक साथ लाने से उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता में वृद्धि हुई। चरण सिंह ने भ्रष्टाचार की उन शिकायतों के खिलाफ, जो उनकी जानकारी में लाई गयीं, सख्त कार्रवाई की।
- **फरवरी 1953:** संशोधित भूमि दस्तावेज नियमावली (1952) ने पटवारियों (ग्राम स्तर पर भूमि दस्तावेजों के प्रभारी), जो किसानों को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते थे, की शक्तियों को उत्तर प्रदेश में काफी कम कर दिया। भू-स्वामी शक्तियों की प्रतिक्रिया ने इन पटवारियों को उकसा दिया, जो कि समझौता वार्ता के जारी रहने के बावजूद हड़ताल पर चले गये। चरण सिंह ने प्रशासनिक दृढ़ता एवं राजनीतिक निपुणता का कदम उठाते हुए सभी 27

हजार पटवारियों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया और उनकी जगह लेखपाल ले आये।

  - उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए नौकरियों में 18% आरक्षण का निर्देश दिया, जिसमें शिक्षा में छूट देने के बावजूद, उपयुक्त अभ्यार्थियों के अभाव के चलते, मात्र 5% भर्ती किये जा सके।

- **1954:** मृदा (मिट्टी) एवं जल संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश *भूमि एवं जल संरक्षण कानून* बनाया, राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में मृदा परीक्षण योजना लागू की गयी।
- **13 सितम्बर 1954:** 30 लाख छोटे जोतदारों, जिन्हें अधिवासी कहा गया, जिनमें 10 लाख अनुसूचित जाति के थे, को भूमि का स्थाई अधिकार प्रदान करने के लिए जेड.ए.एल.आर. कानून में संशोधन किया। उत्तर प्रदेश इकलौता राज्य था, जहां 1952 के जेड.ए.एल.आर. कानून की एक मूल धारा के अन्तर्गत, योजना आयोग की सिफारिशों और उत्तर प्रदेश के भूस्वामियों के दबाव के बावजूद, पूर्व भूस्वामियों (जो स्वयं खेती नही करते थे) को पूर्व जोतदारों से भूमि वापस लेने का अधिकार नहीं दिया गया।
- **1954:** प्रधानमंत्री नेहरू को कानून बनाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा, जो यह सुनिश्चित करता कि केवल वे ही युवा, जिन्होंने अपनी जाति के बाहर विवाह किया है या जाति से बाहर विवाह करने को तैयार थे, उन्हें ही सरकारी राजपत्रित सेवाओं में भर्ती किया जायेगा। उनका मत था कि जाति के दुस्साध्य मुद्दे के विघटन की प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। नेहरू उनके इस प्रस्ताव से असहमत थे, क्योंकि उनका मानना था कि जीवन-साथी को चुनना व्यक्ति के चुनाव की स्वतंत्रता का मुददा है।
- उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में उनकी ख्याति में वृद्धि हुई। अलबत्ता भूस्वामियों (जमींदारों) से शत्रुता मोल ले ली।
  - 27 दिसम्बर 1954: सरदार बल्लभ भाई पटेल के निधन के बाद केन्द्रीय गृहमंत्री के रूप में पंत दल्ली चले गये। 1937 से 1954- उन्होंने किसानों, जो उनके हृदय के सबसे ज्यादा करीब थे, के महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रभावित करने के लिए पंत के साथ बहुत जुड़ाव से काम किया। बाद में 1979 में चरण सिंह ने इस दौर को अपने राजनीतिक जीवन का स्वर्णिम काल कहा।

28 दिसम्बर 1954 - 9 अप्रैल 1957: डा. सम्पूर्णानंद मंत्रिमंडल में राजस्व, अल्पता एवं यातायात विभाग के कैबिनेट मंत्री

- लेखपालों और अमीनों के पदों हेतु अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों की भर्ती में 18 प्रतिशत वृद्धि के आदेश राजस्व बोर्ड की ओर से जिलों को जारी किये गये।
- **जून 1957:** राज्य मंत्रिमंडल को एक नोट में सुझाव दिया कि मंत्रीगण अपने वेतन में 10 प्रतिशत की कटौती करें, आयातित लिमोजिन कारों की जगह छोटी कारों में चलें, अपनी कारों पर राष्ट्रीय झंडा न लगायें, मंत्रियों के साथ सशस्त्र पुलिस न चले, मंत्रियों को सशस्त्र रक्षक न दिये जायें और मुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री के अलावा किसी को पुलिस की सलामी न दी जाये।
    - **1956: 'व्हैदर को-आपरेटिव फार्मिंग' पुस्तक का प्रकाशन।** इलाहाबादः सुपरिंटेन्डेंट, प्रिंटिंग एण्ड स्टेशनरी, यूनाइटेड प्रोविंस, इंडिया 1956।

10 अप्रैल 1957 - 31 मार्च 1958: राजस्व, अल्पता विभाग के कैबिनेट मंत्री

- मां नेत्र कौर का 75 वर्ष की आयु में निधन।
    - **1957: *"एग्रेरियन रिवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश'* पुस्तिका का प्रकाशन।** प्रकाशन शाखा, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, 1957

1 अप्रैल 1958 -16 नवम्बर 1958: राजस्व, अल्पता, वित्त एवं विक्री-कर विभाग के कैबिनेट मंत्री

17 नवम्बर 1958 - 21 अप्रैल 1959: राजस्व, अल्पता, सिंचाई, ऊर्जा एवं विद्युत परियोजना विभाग के कैबिनेट मंत्री

- **9 जनवरी 1959:** नागपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 64 वें अधिवेशन में सोवियत रूस से प्रभावित जवाहरलाल के सहकारी खेती के प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा भारतीय कृषि की निर्णायक नीति के रूप में अपनाये जाने के प्रस्ताव के विरोध में एक घंटा बोले।
- सारी दुनिया में सहकारी खेती की विफलता और खुदकाश्त छोटे किसानों की उच्च उत्पादकता से चरण सिंह की दूरदर्शिता जाहिर हुई।
- **22 अप्रैल 1959:** मुख्यमंत्री सम्पूर्णानन्द के साथ गहराते मतभेदों के चलते मंत्रिमंडल से त्यागपत्र। 1937 से पहली बार 19 महीने के लिए 6 दिसम्बर 1960 तक मंत्रिमंडल से बाहर रहे।
- नागपुर ए.आई.सी.सी. अधिवेशन में अपने सिद्धातों की प्रतिच्छाया में पार्टी के सहयोगियों के साथ-साथ राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व द्वारा उनको अनदेखा किया गया, किन्तु चरण सिंह द्वारा मुख्यमंत्री सम्पूर्णानन्द एवं उनके

सहयोगियों को लम्बे समय से प्रशासनिक रूप से अयोग्य एवं भ्रष्ट पाया गया, जिसके बारे में उन्होंने खुद सम्पूर्णानन्द से लेकर नेहरू और पंत को पत्र लिखे।

- उनके इस्तीफे के पीछे तात्कालिक कारण राज्य सरकार के उस निर्णय का सैद्धांतिक विरोध था, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार ने रिहन्द बाँध से उत्पादित बिजली की किसानों के बजाए बिड़ला ग्रुप के एल्युमिनियम प्रोजेक्ट को सस्ती दरों पर आपूर्ति की।
    - **1959: *"ज्वाइंट फार्मिंग एक्स-रेड: दि प्रॉब्लम एण्ड इट्स सोल्यूशन'* पुस्तक का प्रकाशन** किताबिस्तान, इलाहाबाद, पृष्ठ 322 ।

7 दिसम्बर 1960 - 25 अगस्त 1963: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चन्द्रभानु गुप्ता की सरकार में गृह, पुलिस, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल

- मुख्यमंत्री द्वारा अनदेखी किये जाने पर असंतुष्ट रहे, उनकी राय में इस अनदेखी की वजह उनकी क्षमता और जनता से उनकी प्रतिबद्धता नहीं बल्कि सहकारी खेती के प्रति नेहरू की सनक थी, जिसका उन्होंने विरोध किया था।
- पुलिस की कार्य-शैली का स्वरूप जन-हितकारी बनाने का प्रयास किया, जबकि कार्यस्थितियों के चलते पुलिस बल को होने वाली वास्तविक कठिनाइयों को भी समझा और कार्य किया।
    - कानून लागू करते समय पुलिस अधिकारियों को राजनीतिक हस्तक्षेप से संरक्षित रखने का वचन दिया।
    - भ्रष्टाचार में कमी, यातायात, संचार और तकनीक में सुधार के साथ कांस्टेबलों के अल्प वेतन एवं खराब कार्यस्थितियों में सुधार की आवश्यता पर बल दिया।
    - पुलिस अधिकारी, जो अपराधियों के साथ मुठभेड़ में मारे जाते थे, उनके आश्रितों को वेतन और पूरी पेंशन प्रदान की।
    - पुलिस की नियुक्ति और तबादलों में राजनीतिकों का दबाव मानने से इंकार, विशेषकर पुलिस सब-इंसपेक्टर स्तर पर, जो तब तक संरक्षण और भ्रष्टाचार का एक स्त्रोत था।
    - इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों पर लगे दंगे के केस, मानसरोवर सिनेमा पर लूट का केस और उनकी अपनी पार्टी के विधायकों पे चल रहे कई किस्म के अपराधिक मामलो को उन्होंने वापस लेने से इनकार कर दिया।
- मुख्यमंत्री से मतभेदों के चलते 13 मार्च 1962 को उनसे गृह एवं पुलिस मंत्रालय ले लिया गया।

- 1 अक्टूबर 1963 तक कृषि मंत्री रहे।
    - एक कृषि आपूर्ति संगठन द्वारा सभी किसानों को उन्नत बीज, उर्वरक और कृषि-संयंत्र प्रदान करने के लिए *'1954 भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम'* में सुधार किया।
- उत्तर प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित भू-जोत अधिनियम-1960 द्वारा हदबंदी लागू की गयी, जिसमें उन्होंने विशेष रुचि ली।
    - 1960 में पिता मीर सिंह का 80 वर्ष की आयु में में निधन।
        - पिता समान और मार्ग-दर्शक गोविन्द बल्लभ पंत 7 मार्च 1961 को दिवंगत हो गये।

14 अक्टूबर 1963 - 13 मार्च 1967: कृषि, पशुपालन, मत्स्यपालन एवं वन मंत्री के तौर पर सुचेता कृपलानी मंत्रिमंडल में शामिल हुए।

- **1964**: 1939 से अपूर्ण पड़े, 'कृषि विपणन अधिनियम' को कृषि सम्बंधी गतिविधियाँ को नियमित करने के लिए पारित किया।
- **जनवरी 1964:** छोटे और साधारण किसान को आधुनिक वैज्ञानिक तौर-तरीकों से लाभान्वित करने के लिए राज्य वित्त पोषित कृषक समाज की स्थापना की।
    - 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया।
    - उत्तर प्रदेश में साथी संसदीय सचिव रहे लालबहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री चुने गये।
- **14 मई 1965:** कृषि, पशुपालन एवं मत्स्यपालन मंत्रालय उनसे वापिस ले लिये गये।
- **14 मई 1965 से 13 मार्च 1967:** वन विभाग के कैबिनेट मंत्री।
    - जनवरी 1966 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री चुनी गईं।
    - **1964: *'इंडिया'ज पॉवर्टी एण्ड इट्स सोल्यूशन'* पुस्तक का प्रकाशन,** एशिया पब्लिशिंग हाउस, 1964, पृष्ठ 527। गांधीवादी विमर्ष पर ग्रामोद्योग ढांचे में लघु उत्पादक के लिए यह उनकी आजतक की सबसे बोधगम्य पुस्तक है।

फरवरी 1967: उत्तर प्रदेश विधानसभा में विधायक सीट आजादी के बाद से किसी भी चुनाव में किसी भी उम्मीदवार की अपेक्षा रिकार्ड अन्तर से जीती, 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में चौथी विधानसभा का गठन हुआ।

- **1967 मार्च के शुरू में:** इंदिरा गांधी के दूतों (उमाशंकर दीक्षित और दिनेश सिंह) ने चरण सिंह को कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता पद का चुनाव न लड़ने के लिए राजी कर लिया।
- **13 मार्च 1967:** सी.बी. गुप्ता, जिन्हें बदले में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद देने का वायदा किया गया था, के प्रयासों से दिल्ली में इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई आंशिक रूप से निकट आये।
- **14 मार्च 1967:** चरण सिंह ने सी.बी. गुप्ता मंत्रिमंडल में शामिल होने से इंकार कर दिया, इंदिरा गांधी के दूतों से, दो भ्रष्ट कांग्रेस नेताओं को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल से बाहर रखने का समझौता हुआ था, टूट गया था। उनसे कहा गया कि वह जो चाहें कर सकते हैं।
- कांग्रेस से अलग होने के उनके अंतिम निर्णय को सुनकर कांग्रेस (आर) ने अंतिम पलों में एक मायूस-सा प्रयास किया कि उन्हें मुख्यमंत्री पद देने का समर्थन किया जा सकता है, यदि वह पार्टी में बने रहें। चरण सिंह ने इंकार कर दिया, उन्होंने अपना रास्ता चुनने का मन बना लिया था। इन कठिन हालात में गायत्री देवी ने उन्हें अपने चुने रास्ते पर चलने की सलाह दी।
- **1 अप्रैल 1967: चरण सिंह ने अपने 16 साथियों के साथ अलग होकर जन कांग्रेस का गठन किया।** आजादी के बाद के दौर में जिस संगठन को बनाने में 38 साल की लम्बी अवधि तक मेहनत की, स्वार्थलोलुप कांग्रेसी नेताओं से मोहभंग के बाद उसे छोड़ने की चरण सिंह के लिए विशेष वजहें थीं - गहरे तक फैला भ्रष्टाचार, विकास की गलत नीतियां और पार्टी में नैतिक गिरावट।
    - क्षेत्रीय नेताओं, जिनका संगठन पर नियंत्रण था किन्तु जनसमर्थन नहीं था, के दावों के ऊपर चरण सिह का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की अपनी क्षमता में अटूट विश्वास था। 1960, 1963 और अब 1967 में उनकी अनदेखी की जा चुकी थी; 65 की उम्र में उन नीतियों और योजनाओं को लागू करने, जिन्हें उन्होंने अपने दशकों के राजनीतिक तजुर्बे से विकसित किया था, का समय निकला जा रहा था।
    - अपनी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों में व्यापक रूप से फैलते जा रहे भ्रष्टाचार को वह बेहद नापसंद करते थे और गरीबों के हितों से विमुख होने के कारण उन्होंने उनसे पूरी तरह सम्बंध विच्छेद कर लिया। उनका

विश्वास था कि भ्रष्टाचार या नैतिकता का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है।

- आम लोगों, जिनमें से 80% अभी भी गांवों मे रहते हैं, के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करने वाली कृषि, ग्रामीण विकास, लघु एवं कुटीर उद्योग की पक्षधर नीतियों की अनुपस्थिति ने सब बर्बाद कर दिया।
- वह कार्यपालिका, नौकरशाही और विधायिका को संचालित करने वाले लीवर (नियंत्रण तंत्र) पर से शहरी एवं ऊँची जातियों के नियंत्रण को खत्म करने के पक्षधर थे।

3 अप्रैल 1967 - 25 फरवरी 1968: आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में पहले गैर-कांग्रेसी मुख्यमंत्री के रूप में *संयुक्त विधायक दल* (यूनाइटेड लेजिस्लेचर पार्टी), विपक्ष के जनसंघ, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (एस.एस.पी.), साम्यवादी, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, रिपब्लिकन और निर्दलियों के गठबंधन का नेतृत्व किया। 99 विधायकों के साथ जनसंघ और 45 विधायकों के साथ एस.एस.पी. सबसे बड़े घटक थे।

- चार कैबिनेट मंत्री और दो राज्यमंत्री पिछड़ी जाति से, जो राज्य की जनसंख्या की 55% थी, नियुक्त किये, चार मुस्लिम मंत्री और एक नियुक्ति अनुसूचित जाति से की। यह 1937 से किसी भी मंत्रिमंडल में प्रत्येक समुदाय से उच्चतम प्रतिनिधित्व था।
- उत्तर भारत में एक विशिष्ट शक्ति के तौर पर 'अन्य पिछड़ी जाति'; (ओ.बी.सी.) का ऐतिहासिक उत्थान शुरू हुआ।
- **मई 1967** पटना में - बिहार, यू.पी., बंगाल, उड़ीसा और राजस्थान के पूर्व वरिष्ठ कांग्रेस-जनों द्वारा भारतीय क्रांति दल (बी.के.डी.) का गठन किया गया। 1968 में जन कांग्रेस का बी.के.डी. में विलय हो गया और अप्रैल 1969 में उन्होंने पार्टी की अध्यक्षता ग्रहण की।
- सी. राजगोपालाचारी और उनकी स्वतंत्र पार्टी के विलय की वार्ता हुई, जो कि फलीभूत नहीं हुई। एक संयुक्त पार्टी के लिए उनके मानदंड ऐसे समन्वित संविधान, जिसमें सभी धर्मों के लोगों की सहमति हो, पर आधारित थे।
- विधायकों और मेयर आदि पर एक स्वतंत्र जांच एजेन्सी द्वारा लगे आरोपों की जांच के लिए 'सार्वजनिक जांच अध्यादेश' जारी किया।
- अंग्रेजों द्वारा सहयोगियों को बांटने के लिए बनाया गया ऑनरेरी मजिस्ट्रेट का पद कैबिनेट द्वारा समाप्त करने का निर्णय लिया गयाः 2 अक्टूबर 1967 को न्यायपालिका को कार्यपालिका के हस्तक्षेप से पृथक कर दियाः निर्णय लिया गया कि किसी भी शैक्षिक संस्थान को, जिसके साथ जाति-सूचक शब्द जुड़ा है,

सरकार द्वारा आर्थिक सहायता नहीं दी जायेगी (नतीजतन सभी शिक्षा संस्थानों ने, जिनके नाम जाति से जुड़े थे, शीघ्रता से अपने नाम बदल दिये): उर्दू की तरक्की के लिए कोष जारी किये और 23 मुस्लिम बहुल तहसीलों में सरकारी गजट उर्दू में उपलब्ध कराया; हिन्दी को राज्य प्रशासन की एकमात्र भाषा बनाया; और छोटे खेतों से मालगुजारी कम कर दी। उत्तरी भारत के कई हिस्सों में हिंसा के बावजूद उनके काल में यू.पी. में साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए, दोनों समुदायों के असामाजिक तत्वों के विरुद्ध पुलिस को सभी शक्तियां प्रदान की गयीं और राजनीतिक हस्तक्षेप से अवमुक्त रखा गया।

- अपने घटक दलों की तनातनी के चलते संविद सरकार विघटित हो गयी। जनवरी 1968 में जब प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के सरकारी दौरे पर थीं, चरण सिंह व्यक्तिगत रूप से उनके साथ रहे और उनकी जन-गिरफ्तारी करने की, संविद सरकार के एक घटक सोशलिस्ट पार्टी के नेताओं की धमकियों को व्यर्थ कर दिया - उनके नेता जेल की सलाखों के पीछे कर दिये गये। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और पश्चाताप में डूबे संविद घटकों की मान-मनौबल को पुनर्विचार करने या स्वीकार करने से इंकार कर दिया।
    - उप-चुनाव की घोषणा तक प्रदेश राज्यपाल शासन के अन्तर्गत रहा।

26 फरवरी 1969: उप-चुनाव में उनकी पार्टी बी.के.डी. ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उत्तर प्रदेश में 425 सदस्यों के सदन में, कांग्रेस के 211 विधायकों के बाद 98 सीट लेकर दूसरे नम्बर पर रही।

- बी.के.डी. ने अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह और मतदाताओं के जमीनी समर्थन के चलते अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन संगठन नया और कमजोर था एवं अमीर पूंजीपतियों के महत्वपूर्ण वित्त-पोषण का अभाव था।
- सी.बी. गुप्ता निर्दलियों की सहायता से एक बार पुनः मुख्यमंत्री चुने गये, चरण सिंह नेता विरोधी दल बने।
- बी.के.डी. ने अपने कानपुर अधिवेशन में अपना राजनीतिक नजरिया, जो गांधीवादी ढांचे के अन्तर्गत गांव, कृषि और ग्राम्य-कुटीर उद्योग-धंधों पर आधारित था, स्थापित किया। इसका व्यापक घोषणा-पत्र एक गरीब और कृषक-राष्ट्र के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समन्वित दृष्टि का उदाहरण है।
- एकल पहचान की दृष्टि से जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के साथ विलय को लेकर विचार-विमर्श हुआ; विचार फलीभूत न हुआ।

- 1969 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सी.बी. गुप्ता के नेतृत्व में 90 विधायकों के साथ कांग्रेस (ओ) और कमलापति त्रिपाठी के नेतृत्व में 120 विधायकों के साथ कांग्रेस (आर) (इंदिरा गांधी) में विभक्त हो गई।
    - यहां से इंदिरा गांधी का कांग्रेस के निर्विवाद नेतृत्व के रूप में उद्भव और नई कांग्रेस में स्वतंत्र राज्य नेतृत्व का विनष्ट होना शुरू हुआ। उनकी अधिनायकवादी प्रवृत्ति 1975 के आपातकाल मे अंध-काल के रूप में प्रकट हुई।

17 फरवरी 1970 - 29 सितम्बर 1970: कांग्रेस के दोनों घटकों द्वारा सरकार बनाने के लिए उन तक पहुंच बनाने के बाद चरण सिंह इंदिरा गांधी की कांग्रेस (आर) के समर्थन से दोबारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने।

- भूमिहीनों को हजारों एकड़ भूमि के वितरण-अधिकार, सीरदारी की प्रक्रिया को गति दी।
- उत्तर प्रदेश में शैक्षिक संस्थानों में छात्र-संघों की अनिवार्य सदस्यता को स्वैच्छिक बनाया।
- बी.के.डी. ने लोकसभा में प्रिवीपर्स समाप्ति के विरुद्ध मतदान किया, क्योंकि भारत में विलय के समय सरदार पटेल द्वारा यह एक पवित्र वचन दिया गया था। बी.के.डी. ने कांग्रेस (आर) में विलय से भी इंकार कर दिया और उनके राजनैतिक रिश्ते शीघ्र ही बिगड़ गये।
- चरण सिंह ने मुख्यमंत्री पद छोड़ने से इंकार कर दिया। सभी विधायी परम्पराओं और कानूनी अभिमतों के विरुद्ध राष्ट्रपति शासन थोप दिया गया।
- एक माह बाद राष्ट्रपति शासन की समाप्ति पर कांग्रेस को छोड़कर सभी पार्टियों द्वारा इसरार करने के बावजूद उन्होंने एस.वी.डी. सरकार का मुखिया बनने से इंकार कर दिया और कांग्रेस (ओ) के त्रिभुवन सिंह को नई सरकार के गठन के लिए अपना समर्थन प्रस्तावित किया।

मार्च 1971: इंदिरा गांधी ने 'गरीबी हटाओ' के नारे और बैंकों के राष्ट्रीयकरण के साथ जुलाई 1969 में संसदीय चुनाव की घोषणा की।

- चरण सिंह भारतीय संसद का पहला चुनाव मुजफ्फरनगर से कम्युनिस्ट पार्टी के विजयपाल सिंह,जिनका कांग्रेस (आर) से चुनावी समझौता था तथा उन्हें भारी वित्तीय सहायता दी गयी थी, से हार गये।
- 1977 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विरोधी दल के रूप में लखनऊ में रहे।

फरवरी 1974: बी.के.डी. ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में (425 में से 106 सीटों पर जीत) 21% वोट के साथ अच्छा प्रदर्शन किया किन्तु विपक्ष में विखराव के चलते कांग्रेस के प्रभुत्व को समाप्त नहीं कर सकी।

- 1973 के घोषणा-पत्र में अनुसूचित जाति को फैक्टरियों में, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों, साथ ही परमिट और लाइसेंस में, जिनमें तकनीकी कुशलता की आवश्यकता नहीं थी, 20% आरक्षण प्रस्तावित किया गया।
- **1973**: कांग्रेस के विरोध में सभी राजनीतिक दलों को एक साथ लाने के प्रयास जारी रहे। जनसंघ और कांग्रेस (ओ) साथ-साथ आना नहीं चाहते थे- उदाहरण के लिए मोरारजी देसाई अपनी कांग्रेस (ओ) के लिए सारी सीटों में से आधी चाहते थे।

29 अगस्त 1974: जनतांत्रिक राष्ट्रवादी कदम उठाते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय विकल्प हेतु बी.के.डी., स्वतंत्र पार्टी, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी (राजनारायण), उत्कल कांग्रेस (बीजू पटनायक), राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल (बलराज मधोक), किसान मजदूर पार्टी और पंजाबी खेतीबाड़ी यूनियन के विलय के साथ **भारतीय लोकदल का गठन** हुआ।

- वह एक संविधान और रचनात्मक कार्यक्रम से आबद्ध एक एकल, संयुक्त पार्टी के गठन हेतु निरन्तर प्रयासरत रहे किन्तु दो राष्ट्रीय राजनीतिक दलों - कांग्रेस(ओ) और जनसंघ के अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान छोड़ने के प्रति अनिच्छुक होने और जयप्रकाश नारायण के बिहार में अपनी दल विहीन 'समग्र क्रांति' के प्रयोग में लगे रहने के चलते असफल रहे।
- **16 मार्च 1975:** दिल्ली में जयप्रकाश नारायण, चरण सिंह, प्रकाश सिंह बादल, नानाजी देशमुख और राजनारायण के नेतृत्व में कांग्रेस के विरुद्ध विशाल प्रदर्शन हुआ।
    - **12 जून 1975:** हारे हुए उम्मीदवार राजनारायण की चुनाव याचिका पर इंदिरा गांधी रायबरेली में 1971 के चुनाव अभियान के दौरान सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की दोषी पाई गयीं। उनका चुनाव रद्द हो गया और उन्हें चुनाव लड़ने से 6 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। उन्होंने संविधान निलंबित कर दिया और 25 जून 1975 की रात को आंतरिक आपात स्थिति की घोषणा कर दी।

25 जून 1975 - मार्च 1976: चरण सिंह चौथी बार और आजाद भारत में पहली बार जेल गये। उन्हें तिहाड़ जेल में रखा गया। इंदिरा गांधी द्वारा थोपे गये 21 माह के तानाशाहीपूर्ण आंतरिक आपातकाल में पूरे भारतवर्ष से सैकड़ों राजनीतिक नेतागण और दसियों हजार राजनीतिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार जेलों में डाल दिये गये।

- उन्हें 10 x 16 फीट के बिना खिड़की के कमरे में रखा गया, जिसमें 4 x 6 फीट का शौचालय था। अपनी पुस्तक *'इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडिया'* के लेखन की शुरूआत की। 8 फरवरी 1976 को जनसंघ नेता विजयाराजे सिंधिया तथा नानाजी देशमुख और वरिष्ठ अकाली नेता प्रकाश सिंह बादल एवं अन्य नेताओं, जो वहां मौजूद थे, के साथ विचार-विमर्श के बाद एक संयुक्त राजनीतिक दल ने नया आकार लिया।
- अशोक मेहता एवं अन्य नेताओं के साथ एमनेस्टी इन्टरनेशनल की रिपोर्ट पर बिना नोटिस के जेल से रिहा किये गये।
- **23 मार्च 1976:** रिहाई के बाद आपातकाल की भर्त्सना और इंदिरा गांधी से राजनीतिक विरोध को बल देते हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा में चार घंटे लम्बा ऐतिहासिक भाषण दिया। उनका यह भाषण प्रैस पर पूरी तरह सेंसर लागू होने के कारण जनता के बीच न आ सका।
- कांग्रेस के मुकाबले संयुक्त विपक्ष के एजेण्डे को आगे बढ़ाने के लिए अप्रैल 1976 से 1977 तक अन्य विपक्षी नेताओं के साथ अनेक बैठकें आयोजित कीं। इंदिरा गांधी ने 18 जनवरी 1977 को चुनावों की घोषणा कर दी, जिससे विपक्ष में जान पड़ गई। उत्तरी भारत में संयुक्त जनता पार्टी का पूरा उत्तरदायित्व लेने के लिए मोरारजी देसाई को अध्यक्ष और चरण सिंह को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।

23 जनवरी 1977: जनता पार्टी की स्थापना में मदद की, उनकी पार्टी बी.एल.डी. ने उत्तर भारत में कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त करने के लिए आधारभूत चुनावी ढांचा तैयार किया।

- **24 मार्च 1977:** पहली बार भारतीय संसद के लिए चुने गये।

24 मार्च 1977 - 1 जुलाई 1978: भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई मंत्रिमंडल में केन्द्रीय गृहमंत्री

- कांग्रेस (ओ), जनसंघ, बी.एल.डी. और सी.एफ.डी. घटकों के बीच क्षेत्रीय झगड़ों की शुरूआत, जनता पार्टी में मतभेद गहरा गये। 1 जुलाई 1978 को मोरारजी देसाई ने चरण सिंह को मंत्रिमंडल से हटा दिया।

- **1978:** ***'इंडिया'ज इकोनॉमिक पॉलिसीः दि गांधियन ब्लूप्रिंट*'का प्रकाशन,** विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, पृष्ठ 127 ।

23 दिसम्बर 1978: अपने 76 वें जन्म दिन पर दिल्ली में बोट क्लब पर आयोजित ऐतिहासिक 'किसान रैली' की अध्यक्षता की। कहा जाता है कि आजाद भारत के इतिहास में यह किसानों और ग्रामीणों का सबसे बड़ा जमावड़ा था।

24 जनवरी 1979 - 16 जुलाई 1979: केन्द्रीय वित्त मंत्री और उप-प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी मंत्रिमंडल में वापसी

- संसद में 28 फरवरी 1979 को कृषि, ग्रामीण भारत और लघु उद्योग पर केन्द्रित केन्द्रीय बजट प्रस्तुत किया।
- मोरारजी देसाई के अड़ियल रवैये, जनसंघ घटक की पैंतरेबाजियों, जगजीवन राम और जनता पार्टी अध्यक्ष चन्द्रशेखर की महत्वाकांक्षाओंतथा राजनारायणऔर मधु लिमये की कुछ गलत सलाह से किये गये कार्यों ने जनता पार्टी में टूट का रास्ता तैयार किया।
- चरण सिंह धड़े जनता (सेक्युलर) को 76 सांसदों का समर्थन मिला, उन्हें राष्ट्रपति संजीवा रेड्डी द्वारा सरकार बनाने को आमंत्रित किया गया।

28 जुलाई 1979: कांग्रेस (चव्हाण), अकाली दल, कम्युनिस्ट तथा छोटे दलों के अल्पजीवी गठबंधन और इंदिरा कांग्रेस के 73 सांसदों के बाहर से समर्थन से **भारत के प्रधानमंत्री** पद की शपथ ली।

- चरण सिंह ने आपातकाल की ज्यादतियों के लिए विशेष अदालतों एवं उच्चतम न्यायालय में संजय गांधी पर चल रहे मुकदमों को वापस लेने से इंकार कर दिया। कांग्रेस (आर) ने अपना समर्थन वापस ले लिया। चरण सिंह ने संसद में विश्वासमत का सामना किये बिना 20 अगस्त 1979 को राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे दिया।
- संसद के मध्यावधि चुनाव आयोजित होने तक, 14 जनवरी 1980 तक केयरटेकर प्रधानमंत्री बने रहे।

1980: बागपत, उत्तर प्रदेश से दूसरी अवधि के लिए संसद के लिए चुने गये।

- चुनाव नतीजे उनकी पार्टी लोकदल के लिए एक बड़ा झटका थे। जनता पार्टी के विघटन को जनता ने खारिज कर दिया था, और इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आईं। यद्यपि लोकदल (राष्ट्रीय वोटों के 9.4% वोटों के साथ) संसद की 41 सीटें जीतकर कांग्रेस (आई) के बाद संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप

में उभरा। जगजीवन राम के नेतृत्व में शेष बची जनता पार्टी को संसद की कुल 31 सीटें मिलीं।

- **'इकोनॉमिक नाइटमेयर ऑफ इंडियाः इट्स कॉज एण्ड क्योर' पुस्तक का प्रकाशन,** नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, पृष्ठ 598 ।

1982: लोकदल में विभाजन

- राजनीतिक मतभेदों के चलते मुख्य सहयोगी उन्हें छोड़ गये।
- विपक्षी एकता के प्रयासों में व्यस्त रहे। भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी के साथ चुनावी गठजोड़ के तहत पहला राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन बनाया।

1983 – 1984: राष्ट्रीय मसलों में तल्लीन रहे, सिक्ख उग्रवाद का सार्वजनिक रूप से पूरी ताकत से विरोध किया।

- इंदिरा गांधी और उनकी कांग्रेस के विरोध में राष्ट्रीय राजनीति के केन्द्र बने। 21 अक्टूबर 1984: लोकदल, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस, किसान मजदूर पार्टी, उत्कल कांग्रेस और अन्य छोटे दलों को मिलाकर 'दलित मजदूर किसान पार्टी' का गठन किया।
- 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की घृणित हत्या कर दी गयी और जनता ने उनके पुत्र राजीव गांधी को 542 में से 411 सीटों के साथ ऐतिहासिक महाविजय प्रदान की।
- चरण सिंह अपनी पार्टी के तीन सांसदों सहित, बागपत से तीसरी और अंतिम बार सांसद चुने गये।

25 नवम्बर 1985: उन्हें मस्तिष्क का आघात लगा, जिसने अगले 18 माह के लिए उन्हें निष्क्रिय बना दिया ।

- 14 मार्च 1986: अमेरिका के बाल्टीमोर स्थित जॉन हॉपकिन्स अस्पताल में इलाज हुआ, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। वह कोमा में चले गये।

29 मई 1987: 85 वर्ष में 7 माह कम रहने के चलते 29 मई को निधन हो गया।

- **दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि के पार्श्व में *'किसान घाट'* पर उनका अंतिम संस्कार हुआ और वह अमर हो गये।**

स्त्रोत

फरवरी 1994 में चरण सिंह की पत्नी श्रीमती गायत्री देवी द्वारा नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, नई दिल्ली (NMML) को प्रदान किये गये ऐतिहासिक तथ्यों से समावेशित 'चरण सिंह पेपर्स' (C.S. Papers) की संख्या 30 हजार से ऊपर है। इन पेपर्स में चरण सिंह द्वारा अपने साठ वर्ष के सार्वजनिक जीवन के बारीकी से इकट्ठा किये गये दस्तावेजी विवरण शामिल हैं, जो उनके जीवन एवं कार्यों के विभिन्न पहलुओं पर भावी शोध के एक स्त्रोत हैं। सबसे शुरूआती दस्तावेजों में संयुक्त प्रांत में 'किसान संतानों' को सरकारी नौकरियों में आरक्षण से सम्बंधित 1939 का हस्तलिखित दस्तावेज है और सबसे नया अक्टूबर 1985 की उनकी पुस्तक 'राईज एण्ड फॉल ऑफ दि जनता पार्टी' की अधूरी पाण्डुलिपि है। (सी. एस. पेपर्स की अनुक्रमाणिका / क्रमसूची https://charansingh.org/archives पर है) चरण सिंह अभिलेखागार ने 2013 से चरण सिंह के हजारों फोटोग्राफ्स, वीडियोज, भाषण, उन पर लिखीं जीवनियों, उनके द्वारा लिखी गयी सभी पुस्तकों, तथा लखनऊ और दिल्ली में दिये उनके विधायी भाषणों का एकत्रीकरण किया है।

मैंने चरण सिंह के उनके अपने शब्दों पर भारी विश्वास किया है, क्योंकि वह प्रखर इतिहास बोध से सज्ज ब्यौरेवार लिखित प्रमाण रखने वाले व्यक्ति थे। इन पेपर्स में से कुछ हैं: सी.एस. पेपर्स किस्त-II ,सब्जेक्ट फाईल #49, 'चरण सिंह का बायो-डाटा...', सी.एस. पेपर्स किस्त-I-III,: 99 पृष्ठ की पुस्तिका 'हू इज ए कुलकः लेट लैण्ड रिफार्म्स ऑफ यू.पी. टेस्टिफाई; बाई चरण सिंहः अध्याय-1 और अन्यों में हैं 'लैण्ड रिफार्म्स इन यू.पी. एण्ड दि कुलक्स', विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1986 किस्त-II, सब्जेक्ट

फाईल #49 'बायो-डाटा ऑफ चरण सिंह'; किस्त-II, सब्जेक्ट #416 'लाईफ स्केच ऑफ चरण सिंह'; एवं 1972 में लखनऊ में एन.एम.एम.एल. के लिए लिया गया साक्षात्कार।

दूसरा ऐतिहासिक स्त्रोत उनके जीवनकाल में और उनके बाद ऐसे लेखकों, जिन्होंने उनके साथ पर्याप्त समय व्यतीत किया, द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। मैंने जिन प्रकाशनों को प्रमुख समझा, उनसे तिथियों और घटनाओं का सत्यापन किया है, वे इस प्रकार हैं: शर्मा, जयदेव, सम्पादक, प्रताप; **परंतप**, देशभक्त मोर्चा प्रकाशन, 1978; पाण्डेय अनिरुद्ध, **धरती-पुत्र चौधरी चरण सिंह**, ऋतु प्रकाशन, 1986; गोयल, सुखवीर सिंह, **ए प्रोफाइल ऑफ चौधरी चरण सिंह** 1978; सिंह, नत्थन, **किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह** (1902-1987), नई दिल्ली, किसान ट्रस्ट, 2002।

अन्ततः, पॉल ब्रास एक प्रेरणा-स्त्रोत रहे हैं, पॉल ने 1960 से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्षेत्रीय राजनीति पर अपने शोध की विस्तृत सामग्री मेरे साथ उदारतापूर्वक साझा की। चरण सिंह के एक आत्म-स्वीकृत प्रशंसक, परन्तु किसी भी तरह से समालोचना के सिद्धांतों के प्रतिकूल नहीं, पॉल का 25 सितम्बर 1993 के 'इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटीकल वीकली' में प्रकाशित लेख 'एन इंडियन पॉलिटिकल लाईफ' चरण सिंह की राजनीतिक यात्रा का मुख्तसर (थोड़े में पर्याप्त) और प्रवाहपूर्ण कथात्मक वर्णन है।

पॉल ने 1981 में चरण सिंह से उनकी राजनीतिक जीवनी लिखने का अनुमोदन प्राप्त किया था (जिसके लिए उन्हें चरण सिंह द्वारा बड़ी संख्या में संग्रहीत उनके कागजात देखने की पूरी स्वतंत्रता प्रदान की गयी थी), जो कि पॉल के पछतावे के साथ, 1987 में श्री सिंह के निधन के काफी वर्ष बाद 2011 में प्रकाशित हुई। आज ये तीन खण्डों में उपलब्ध हैं 'एन इंडियन पॉलिटिकल लाईफः चरण सिंह एण्ड कांग्रेस पॉलिटिक्स', खण्ड 1, 1937-61 (2011), खण्ड 2, 1957-67 (2012) और खण्ड 3, 1967-87 (2014)। सेज पब्लिकेशंस, दिल्ली।

उनकी विद्वता ने यह संक्षिप्त जीवनी लिखने के लिए मुझे प्रेरणा दी, और इसके लिए मैं श्री पॉल का सदैव आभारी रहूँगा।

हर्ष सिंह लोहित
गुडगाँव
29 मई 2019

अंतिम टिप्पणियां

i. चरण सिंह द्वारा टिप्पणियां, 1982। चरण सिंह पेपर्स, नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी, दिल्ली। किस्त -I,फाइल 1, पृष्ठ 3, अब के बाद 'सी.एस. पेपर्स, एन. एम. एम. एल. के तौर पर उद्धृत किये जायेंगे।

ii . राजा नाहर सिंह (121 गांवों की रियासत बल्लभगढ़ का सामन्त) बगावत में अपनी भूमिका के लिए झज्जर, दादरी और फर्रुखनगर के नवाबों तथा 17 सिपाहियों के साथ अंग्रेजों द्वारा, 1857 में दिल्ली के चांदनी चौक में फांसी पर लटका दिया गया था। इसके बाद अंग्रेजों ने राजा की रियासत कब्जे में ले ली और उसके परिवार और समुदाय को भागने को विवश कर दिया। सिंह, हरि "बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह और 1857 की क्रांति।" इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की अधिकृत रिपोर्ट्स, खंड 52, 1991, पृष्ठ संख्या 587-597, JSTOR, JSTOR, www.jstor.org/stable/44142662. मीर सिंह के पिता बादाम सिंह नाहर सिंह के कुनबे के सदस्य थे और 1960 में आज के फरीदाबाद जिले (हरियाणा) के सीही गांव में आकर बस गये। परंतप, 1978, देशभक्त मोर्चा, कानपुर एवं नई दिल्ली, सम्पादन, माधवी लता शुक्ल, जयदेव शर्मा, एवं एस.पी. मेहरा, पृष्ठ 13-21

iii. कैप्टन आर.एस.राना द्वारा लिखित चरण सिंह की जीवनी की अप्रकाशित पाण्डुलिपि। यह पृष्ठ चरण सिंह द्वारा अनुमोदित है। सी.एस. पेपर्स एन. एम.एम.एल., किस्त-II, एफ-457,पृष्ठ 2

iv. चरण सिंह धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलने वालों में से नहीं थे, किन्तु न ही वे इस बारे में कतई शर्मिंदा थे। पॉल ब्रास के साथ अप्रकाशित साक्षात्कार, 1982, लेखक की व्यक्तिगत जानकारी।

v. रिडले, एच.एच. और गैट, ई.ए। भारत की जनगणना 1901, वाल्यूम-1, पार्ट-II-तालिकाएं पृष्ठ 108-157, कलकत्ता।

vi. ब्रास, पॉल। *चौधरी चरण सिंह एन इंडियन पॉलिटिकल लाइफ*, इकोनॉमिक एण्ड पॉलिटिकल वीकली, इंडिया, 25 सितम्बर 1993.

vii. 4 नवम्बर 1983 को स्वामी दयानन्द की निर्वाण शताब्दी (पुण्य तिथि) पर चरण सिंह द्वारा दिया गया भाषण। सी.एस. पेपर्स एन.एम.एम.एल., किस्त-II, पृष्ठ 452। चरण सिंह अपनी ही अवधारणा को प्रस्तुत करते दिखे हैं, जब उन्होंने लिखा, "यद्यपि विनम्र दयानन्द को अपने मत की अभिव्यक्ति में न हिचकिचाहट थी, न वह उससे पीछे हटने वाले थे, बल्कि अपने बोले गये शब्दों पर अटल थे। वह एक पैदाइशी योद्धा थे और जब सवाल सिद्धांतों का था, उन्होंने कभी नहीं सोचा कि कैसे। परिणाम की चिंता किये वगैर उन्होंने सच को सच और गलत को गलत कहा। दयानन्द अपने सम्पूर्ण विरोधियों के मध्य ओक वृक्ष की भांति, जो तमाम तूफानों के बीच तन कर खड़ा रहता है, तमाम अपमान, अंधविश्वासों और झूठी आस्थाओं के विरुद्ध तन कर खड़े रहे। चौधरी चरण सिंह द्वारा स्वामी दयानन्द की पचासवीं पुण्य तिथि, 4 जून 1933 को हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित लेख से उद्धृत अंश।

viii. पूर्वोक्त।

ix. श्यामलाल मनचंदा द्वारा चौधरी चरण सिंह से लिये गये साक्षात्कार में, एन.एम.एम.एल., ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट, 10 फरवरी 1972, लखनऊ, उ.प्र. https://charansingh.org/archives/interview-nehru-memorial-museum-and-library

x. *परंतप*, 1978, चौधरी चरण सिंह से साक्षात्कार, पृष्ठ 194

xi. श्यामलाल मनचंदा द्वारा चौधरी चरण सिंह से लिये गये साक्षात्कार में, एन.एम.एम.एल., ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट, 10 फरवरी 1972, लखनऊ, उ.प्र. https://charansingh.org/archives/interview-nehru-memorial-museum-and-library लेखक की व्यक्तिगत जानकारी।

xii. 3 जुलाई 1979 को उप-प्रधानमंत्री एवं केन्द्रीय वित्तमंत्री चरण सिंह की ओर से प्रधानमंत्री मोराजी देसाई को लिखा पत्र। 31 मार्च 1979 को सम्पत्तियों एवं देनदारियों का विवरण। अचल सम्पत्ति का ब्यौरा- पत्नी गायत्री देवी द्वारा 191-ए, साकेत, मेरठ की जमीन/भूखण्ड पर निर्माण। चल सम्पत्ति- आभूषणः पाँच नग जड़ी अंगूठियां। बैंक में बचत खाते में 3841.09 रुपये की राशि और कुल 15000 रुपये के विजया कैश सर्टिफिकेट्स। सी.एस. पेपर्स एन.एम.एम.एल., किस्त-II फाईल 322।

xiii. प्रेस के साथ वार्तालाप, 1979। सी.एस. पेपर्स, एन.एम.एम.एल.।

xiv. *इंडियाज़ इकोनॉमिक पालिसीः दि गांधियन ब्लूप्रिंट*, चरण सिंह, विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली 1978। पृष्ठ 43, 91।

xv. कैप्टन आर.एस. राणा द्वारा चौधरी चरण सिंह की अप्रकाशित जीवनी की पाण्डुलिपि। यह पृष्ठ चौधरी चरण सिंह द्वारा अनुमोदित है। सी.एस. पेपर्स एन.एम.एम.एल., किस्त - II एफ-457, पृष्ठ 13

xvi. सी.एस. पेपर्स, एन.एम.एम.एल., किस्त - II फाईल- 49, चरण सिंह का बायो-डाटा... सी.एस. पेपर्स एन.एम.एम.एल.।

xvii. चरण सिंह श्यामलाल मनचंदा के साथ एक साक्षात्कार में, एन.एम.एम.एल., ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट, 10 फरवरी 1972, लखनऊ, उ.प्र.।

xviii. सिंह, चरण, 'किसान संतानों के लिए 60 प्रतिशत नौकरियां क्यों आरक्षित होनी चाहिए' 21 मार्च 1947। एन.एम.एम.एल., सी.एस. पेपर्स, किस्त - I एफ-2।

xix. 1979 में पं. गोविन्द बल्लभ पंत की 92 वीं जयन्ती पर चरण सिंह का भाषण। सी.एस. पेपर्स एन.एम.एम.एल.। किस्त - II

xx. सिंह, ज्ञानी जैल, 'कितनी खूबियां थीं इस इंसान में', 'असली भारत', दिसम्बर 1990, पृष्ठ 20। सी. एस. पेपर्स एन.एम.एम.एल.।

xxi. सरकार की अर्थनीति पर उनकी नजर रहती थीः भ्रष्टाचार के विरुद्ध चरण सिंह का संघर्ष, टाइम्स ऑफ इंडिया, 28 अप्रैल 1959।

xxii. *'परंतप'*, 1978, चरण सिंह से साक्षात्कार, पृष्ठ 195।

xxiii. सिंह, चरण, गांधी जी की ओर, *परंतप* 1978, पृष्ठ 367।

xxiv. *'परंतप'*, 1978, चरण सिंह से साक्षात्कार, पृष्ठ 195।

xxv. चरण सिंह, सी.एस. पेपर्स एन.एम.एम.एल., किस्त - II एफ-457, पृष्ठ 72।

xxvi. सी.एस. पेपर्स एन.एम.एम.एल., किस्त - I राज्य कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन के मुद्दे पर 21 अप्रैल 1967 को चरण सिंह द्वारा टिप्पणी।

xxvii. सक्सेना, एन.एस., इंडियाः टूवर्ड्स एनार्की (भारतः अराजकता की ओर), 1967- 1992, अभिनव प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993, सक्सेना भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी थे। वह उत्तर प्रदेश पुलिस के भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल (डी.जी.) एवं केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के महानिदेशक पद से रिटायर हुए। सक्सेना 197 में उत्तर प्रदेश पुलिस के डी.जी. थे, जब चरण सिंह मुख्यमंत्री थे।

xxviii. उत्तर प्रदेश पुलिस दंगा नियंत्रण में सक्षम, टाइम्स ऑफ इंडिया, 1985, एन.एस. सक्सेना द्वारा। सक्सेना भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी थे। उत्तर प्रदेश पुलिस के भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल (डी.जी.), वह केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के महानिदेशक पद से रिटायर हुए।

xxix. *'परंतप',* 1978, चरण सिंह से साक्षात्कार, पृष्ठ 194।

xxx. चरण सिंह, श्यामलाल मनचंदा के साथ एक साक्षात्कार में, एन.एम.एम.एल., ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट, 10 फरवरी 1972, लखनऊ, उ.प्र. https://charansingh.org/archives/interview-nehru-memorial-museum-and-library

xxxi. एक भूतपूर्व कम्युनिस्ट के साथ व्यक्तिगत साक्षात्कार (1971 के चुनाव में कांग्रेस के एक सहयोगी) एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, 16 मार्च 2015। चरण सिंह के एक राजनीतिक सहयोगी के पुत्र, 1977 से 85 की अवधि में वह चौधरी चरण सिंह का समर्थक बन गया। उसने मुजफ्फरनगर चुनाव में चरण सिंह को हराने के लिए कांग्रेस के कोषाध्यक्ष से व्यक्तिगत रूप से बड़ी मात्रा में धनराशि लेना सुनिश्चित किया, यह एक दिग्भ्रमित विपक्षी का कार्य था, उसने स्वीकार किया कि यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी।

xxxii. सिंह, चरण, *इंडियाज़ पॉवर्टी एण्ड इट्स सोल्यूशन*, 1964, एशिया पब्लिशिंग हाउस, नेशनल पब्लिशिंग, पृष्ठों की संख्या 527, पृष्ठ 115

xxxiii. *'परंतप', चरण सिंह से साक्षात्कार, 1978 और अरविन्द वर्मा आई.पी.एस, 1998*

xxxiv. http://humanrightsinitiative.org/old/index.php?option=com_content&view=article&catid=91%3Ashiva&id=686%3Apolice-india-national-police-commission&Itemid=98

xxxv. http://ncm.nic.in/Genesis_of_NCM.html

xxxvi. https://www.indiatoday.in/magazine/15-01-1979 किसान रैली मात्र चरण सिंह के चोट खाये अहम को सहलाने के लिए आयोजित की गई थी

xxxvii. उप-प्रधानमंत्री एवं वित्तमंत्री चरण सिंह द्वारा 28 फरवरी 1979 को वर्ष 1979-80 का बजट पेश करते समय दिया गया भाषण, सी.एस. पेपर्स, एन.एम.एम.एल.। किस्त - III, अभी तक अनुक्रमित नहीं किया गया है। https://www.indiabudget.gov.in/bspeech/bs197980.pdf

xxxviii. रामचन्द्रन, जी., 'Walking With Giants', 2013, पृष्ठ 192-193 जिस समय चौधरी चरण सिंह वित्तमंत्री थे, उस समय 1978 में रामचन्द्रन भारत सरकार के वित्त सचिव थे।

xxxix. भूतपूर्व केन्द्रीय मंत्री सत्यप्रकाश मालवीय द्वारा 2002 में लिखा लेख, सी.एस. पेपर्स, एन.एम.एम.एल., किस्त - III, अभी तक अनुक्रमित नहीं किया गया है। http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/49084/11/11_chapter2.pdf

xl. सिंह, चरण, The Rise and Fall of the Janata Party, खण्ड - 1 एवं खण्ड - 2, 1985. अप्रकाशित एवं अपूर्ण पाण्डुलिपि, चरण सिंह, अक्टूबर 1985, सी.एस. पेपर्स, किस्त - III, एन.एम.एम.एल.। नवम्बर 1985 में चरण सिंह को मस्तिष्क का आघात लगा, और वह जनता पार्टी की टूट पर लिखी पुस्तक पूरी करने में असमर्थ हो गये। यह पाण्डुलिपि इसे एक काल्पनिक जोड़-तोड़ के रूप में परिभाषित करती है, जिसमें वह इसकी वजह दिखने के बजाए, इसके शिकार दिखते हैं।

xli. http://rural.nic.in/about-us/about-ministry

xlii. प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह क ICRISAT, हैदराबाद में 30 अगस्त 1979 को, उदघाटन भाषण। https://charansingh.org/archives/inaugural-address-international-crops-research-institute-semi-arid-tropics-icrisat-Patan.

xliii. 3 दिसम्बर 1979 को प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह द्वारा ओ.बी.सी. के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण पर कैबिनेट का नोट। सी.एस. पेपर्स, किस्त - III, एन.एम.एम.एल.। अभी तक अनुक्रमित नहीं।

xliv. बायर्स, टेरेंस, *चरण सिंह, 1902-87: एन एसेसमेंट।* ; कृषक - अध्ययन की पत्रिका (जर्नल), 1988, 15:2, 139-189

xlv. चरण सिंह द्वारा प्रकाशन, 2018 https://charansingh.org/books यह भी देखें https://charansingh.org/life-history/ अनेक पुस्तकों में उनकी पहली पुस्तक *'ज़मींदारी उन्मूलनः दो विकल्प'* की संदर्भ ग्रंथ सूची के लिए देखिये, जो पुस्तकें उन्होंने 1947 से पढ़ी थीं, जब उन्होंने अंग्रेज़ी में लिखी अपनी कई पुस्तकों में से पहली पुस्तक लिखी।

xlvi. लेखक की व्यक्तिगत जानकारी

xlvii. सी.एस. पेपर्स, एन.एम.एम.एल.। किस्त - III, फाईल 457, पृष्ठ 97। 29 मई 1987 को चरण सिंह की मृत्यु के समय उनकी सम्पत्तियों में एक पुरानी फिएट कार, बचत खाते में 5000 रुपये से भी कम की राशि और उनकी पत्नी गायत्री देवी द्वारा मेरठ शहर, साकेत में छोटे से भूखण्ड पर निर्मित एक मकान था। एण्डनोट xi भी देखें।

NOTES

चरण सिंह का जन्म 23 दिसम्बर 1902 को संयुक्त प्रांत (उत्तर प्रदेश) के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में "एक साधारण किसान के यहां छप्पर छवाये मिट्टी की दीवारों से बने घर में हुआ था .... जहां आंगन में एक कुआं था, जिसका पानी पीने और सिंचाई के काम आता था।"* एक बटाईदार, गरीब किसान की कच्ची मढ़ैया में पैदा हुआ यह शिशु आज़ाद भारत में देहात की सबसे प्रख्यात और बुलंद आवाज़ बना।

कांग्रेस राष्ट्रवादी तथा स्वतंत्रता सेनानी से विख्यात राजनीतिज्ञ बनने की रोचक कहानी, तथा गांधीवादी परिप्रेक्ष्य में कृषि, गांव और ग्रामीण कुटीर उद्योगों के विकास के वैकल्पिक चिंतन को सुस्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने वाले एक ग्रामीण बुद्धिजीवी की यह एक संक्षिप्त जीवनी है।

---

* चरण सिंह की टिप्पणी, 1982. चरण सिंह पेपर्स, नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली।

चरण सिंह अभिलेखागार

www.charansingh.org

ISBN 978-9-38728-042-7

9 789387 280427 >

मूल्य रु. 299